



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2018/पौष 15, 1939

No. 12]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2018/PAUSHA 15, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2018

अंतिम जांच परिणाम

**विषय :— चीन जन.गण. चीनी ताईपेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एवं कोरिया आर पी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नाइलॉन फिलामेंट यार्न के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।**

**फा. सं. 15/17/2016-डीजीएडी .—** समय-समय पर यथा संशोधित (जिसे यहां इसके बाद अधिनियम भी कहा गया है) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उनकी समय-समय पर यथासंशोधित (जिसे यहां आगे नियमावली भी कहा गया है), सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली 1995 के संबंध में; निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/5/2005- डीजीएडी दिनांक 4 जुलाई, 2005 के अनुसार चीन जन.गण., चीनी ताईपेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एवं कोरिया आर पी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नाइलॉन के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न जिसे पालियामाइड यार्न के रूप में भी जाना जाता है और नाइलॉन फिलामेंट यार्न के रूप में वर्णित किया जाता है, के आयात के विरुद्ध एक पाटनरोधी जांच आरंभ की गई है और प्रारंभिक जांच परिणाम 3 फरवरी, 2006 को प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए थे। प्राधिकारी ने चीन जन.गण., चीनी ताईपेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एवं कोरिया आर पी के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नाइलॉन फिलामेंट यार्न के आयातों पर निर्णायक शुल्कों के अधिरोपण की सिफारिश करते हुए 3 जुलाई, 2006 को अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए 1 सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 85/2006 दिनांक 29 अगस्त, 2006 के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुओं पर निर्णायक पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित किए गए थे।

2. और जबकि, प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 15/4/2010-डीजीएडी दिनांक 19 नवंबर, 2011 के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, निर्णायक समीक्षा जांच की और पाटनरोधी शुल्क के

अधिरूपण को जारी रखने की सिफारिश की। तदनुसार, अधिसूचना सं. 3/2012-सीमा शुल्क दि. 13 जनवरी, 2012 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा निर्णायक पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार किया गया।

3. जबकि, मै. जे सी टी लि., मै. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लि. (जीएसएफसी), मै. गुजरात पोली फिलम्स प्रा.लि. (जी पी पी एल), मै. प्रफुल्ल ओवरसीज प्रा.लि. और मै. ए वाई एम सिनटैक्स लि. (जिन्हें यहां इसके बाद “याचिकाकर्ता” या “आवेदक” भी कहा गया है) ने चीन जन.गण., ताइवान, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एवं कोरिया पी आर (जिन्हें यहां इसके बाद संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नाइलॉन फिलामेंट यार्न (जिन्हें यहां इसके बाद संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा को आरंभ करने के लिए अधिनियम और नियमावली के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां इसके बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष वर्तमान मामले में एक आवेदन दायर किया है और संबद्ध देशों के मूल अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्कों के विस्तार के लिए अनुरोध किया है।

4. और जबकि, प्राधिकारी ने यह जांच करने के लिए कि क्या संबद्ध देशों से मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर उक्त शुल्कों को समाप्त करने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, अधिसूचना सं. 15/17/2016- डी जी ए डी दिनांक 9 जनवरी, 2017 के अनुसार निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत के औचित्य को सिद्ध करने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर एक पब्लिक नोटिस जारी किया। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की वैधता को केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 4/2017-सी.शुल्क (एडीडी) दिनांक 19 जनवरी, 2017 के अनुसार 12 जनवरी, 2018 तक बढ़ाया गया है।

5. वर्तमान समीक्षा के कार्य क्षेत्र में संबद्ध देशों के मूल अथवा वहां से निर्यातित उक्त वस्तुओं के आयातों के संबंध में मूल जांच के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

#### क. प्रक्रिया

6. प्राधिकारी द्वारा उक्त जांच की शुरुआत अधिसूचित करते हुए पब्लिक नोटिस को जारी करने के पश्चात्, इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित कार्य विधि का अनुसरण किया गया है:-

- (i) प्राधिकारी ने ऊपर नियम 5 के उपनियम (5) के अनुसरण में जांच आरंभ करने से पूर्व पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों/प्रतिनिधियों को अधिसूचित किया।
- (ii) प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे जांच शुरुआत अधिसूचना के जारी होने के 40 दिनों के भीतर लिखित में उनके विचार भेजने का अनुरोध किया।
- (iii) प्राधिकारी द्वारा ऊपर नियमावली के नियम 6(3) के अनुसरण में भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन के अगोपनीय रूपांतरण की एक प्रति उपलब्ध कराई गई।
- (iv) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से भी संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर भेजने की सलाह देने का भी अनुरोध किया गया। संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नामों और पतों के साथ उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए प्रश्नावली की एक-एक प्रति भी भेजी गई।
- (v) नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को भी प्राधिकारी द्वारा निर्यातक प्रश्नावली और अनुपूरक प्रश्नावली भेजी गई:-

- (क) मै. पी टी सुसिलिया इंडाह सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज, इंडोनेशिया
- (ख) मै. पी.टी. इंडाची प्राइमा, इंडोनेशिया
- (ग) मै. रिफ्रान (मलेशिया) एस डी एम, बी एच डी, मलेशिया
- (घ) मै. ह्योसंग कारपोरेशन, कोरिया
- (ङ) मै. वूंगजिन केमिकल्स कं. लि.
- (च) मै. सनटैक्स फाइबर्स, ताइवान
- (छ) मै. थाई टफैटा कं. लि., थाईलैंड

- (vi) उपर्युक्त अधिसूचना की प्रतिक्रिया में, निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने उत्तर दिया और प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत किए:-
- (क) मै. पी टी इंदाची प्राइमा
  - (ख) मै. रिक्कान (मलेशिया) एस डी एन बी एच डी
  - (ग) मै. पी टी सुलिंदाफिन
- (vii) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसरण में आवश्यक जानकारी की मांग करते हुए भारत में संबंध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:-
- (क) ब्रेक्स इंडिया प्राइवेट लि.
  - (ख) बालिगा फिशनेट
  - (ग) बिरला केबल लि.
  - (घ) डी सी मिल्स प्रा. लि.
  - (ङ) एंट्रीमोड पॉली कोटर्स लि.
  - (च) गोयंका इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
  - (छ) आई डी एल इंडस्ट्रीज लि.
  - (ज) विविलोन टेक्साटाइल इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
  - (झ) गार्डन सिल्क मिल्स लि.
  - (ञ) एस के एक्सपोर्टर्स
  - (ट) शालोन सिल्क इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
  - (ठ) सुअरटेक्स इंडस्ट्री प्रा.लि.
  - (ड) वालसन पोलिएस्टर लि.
  - (ढ) सुप्रीम इंडिया इंपैक्स लि.
  - (ण) सूरत सिंथेटिक्स लि.
  - (त) सरला परफार्मेंस फाइबर्स लि.
  - (थ) कायवलॉन इंपैक्स प्रा.लि.
  - (द) यूरो विस्ता इंडिया लि.
  - (ध) एस आर एफ लि.
  - (न) हाबासित इयाकोका प्रा.लि.
  - (त) गरवारे वाल रोप्स लि.
  - (प) डूपोंट फाइबर्सलि.
  - (फ) चिदंबरम फिशनेट्स प्रा.लि.
  - (ब) बायर्स इंडिया लि.
  - (भ) एएसयू टेक्साटाइल्स प्रा.लि.
- (viii) संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित आयातकों ने प्रश्नावली उत्तर दायर कर प्रतिक्रिया प्रस्तुत की:-
- (क) मै. परगो इंडिया प्रा. लि.

- (ख) मै. दया निटर्स
- (ग) मै. गिंजा इंडस्ट्रिज लि.
- (घ) मै. मिलान टैक्सटाइल्स
- (ix) इसके अतिरिक्त, संबद्ध वस्तुओं के आयातकों में से एक मै. सरला परफॉर्मेंस लिमिटेड ने पाटन रोधी शुल्क के अधिरोपण का विरोध करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया है।
- (x) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण के लिए एक खुली सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतरण प्रस्तुत किया है।
- (xi) पिछले 3 वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदेवार विवरण उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस) से अनुरोध किया गया, जिसे प्राधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा के परिकलन और सौदों की उचित जांच के पश्चात अपेक्षित विश्लेषण के लिए डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों का सहारा लिया है।
- (xii) उत्पादन की इष्टतम लागत पर आधारित गैर-क्षतिकारक कीमत (एनआईपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के निर्माण और बिक्री के प्रति लागत को यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है कि क्या पाटन मार्जिन से निम्न पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होंगे।
- (xiii) इस तथ्य पर विचार करते हुए कि संबद्ध वस्तुएं विभिन्न ग्रेडों/आकारों/आयामों में आयात की जा रही हैं, आवेदक ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के परिकलन के लिए पीसीएन से पीसीएन तुलना करने के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) का प्रस्ताव किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने पाटन और क्षति मार्जिनों के परिकलन के उद्देश्य से पीसीएन से पीसीएन की तुलना की है।
- (xiv) प्राधिकारी ने 14 नवम्बर, 2017 को आयोजित मौखिक सुनवाई में नियम 6(6) के अनुसरण में मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान किया जिसमें घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी पक्षकार, जिन्होंने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रकट किए थे, उनसे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए अपने विचारों का निवेदन लिखित में प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। हितबद्ध पक्षकारों से विरोधी पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित निवेदनों को भी संग्रहित करने की सलाह दी गई और उन्हें उस के पश्चात् अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का परामर्श दिया गया।
- (xv) आवश्यक समझी गई सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन किया गया। आवश्यक परिशोधनों के साथ सत्यापन की गई केवल ऐसी सूचना पर ही, जहां भी प्रयोज्य था, विश्वास किया गया है।
- (xvi) वर्तमान समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल, 2015 से सितम्बर, 2016 (18 महीने) है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में शामिल अवधि अप्रैल 2012-मार्च 2013, अप्रैल 2013-मार्च 2014, अप्रैल 2014-मार्च 2015 और पीओआई है।
- (xvii) इस जांच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों का प्राधिकारी द्वारा इस प्रकटीकरण विवरण में, जहां भी संगत पाया गया, उल्लेख किया गया है।
- (xviii) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है। संतोषजनक पाए जाने पर, प्राधिकारी ने, जहां भी जरूरी था, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा गया है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों से, गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
- (xix) वर्तमान जांच की अवधि के दौरान जब भी कोई हितबद्ध पक्षकार ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने से मना करता है अथवा अन्यथा रूप से अनिवार्य सूचना उपलब्ध नहीं कराता तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने मत/निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।

(xx) “\*\*\*” इस दस्तावेज में गोपनीय आधार पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत सूचना का प्रतिनिधित्व करता है और इसे नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा इसी प्रकार समझा जाएगा।

(xxi) प्राधिकारी द्वारा पी ओ आई के लिए अपनाई गई विनिमय दर रुपए 66.53 = 1 अमरीकी डॉलर है।

## **ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु**

### **ख. 1. घरेलू उद्योग के विचार**

7. घरेलू उद्योग के विचार निम्नानुसार हैं:-

i. वर्तमान समीक्षा द्वितीय निर्णायक समीक्षा है। मूल जांच और पिछली जांचों में और वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल उत्पाद नायलॉन सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है जिसे पॉलीयामाइड यार्न के रूप में भी जाना जाता है और नायलॉन फिलामेंट यार्न के रूप में वर्णित किया जाता है। वर्तमान निर्णायक समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद वही उत्पाद है जिसे प्राधिकारी द्वारा मूल जांच में अपनाया गया था। नायलॉन फिलामेंट यार्न आर्गेनिक मोनोमर्स के पॉलीमेराइजेशन द्वारा उत्पादित एक सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है।

ii. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की सीमा शुल्क उप-शीर्ष सं. 5402 के तहत शीर्ष अध्याय 54 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और संबद्ध जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

iii. घरेलू और आयातित उत्पाद में नियोजित प्रौद्योगिकी और उनकी गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। वर्तमान जांच एक समीक्षा जांच है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु की जांच की है, जिस पर भरोसा किया गया है।

### **ख.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

8. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:-

- (i) मोनो फिलामेंट यार्न के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किसी क्षति का सामना नहीं किया जा रहा है और आयात भी निम्न है इसलिए मोनो फिलामेंट यार्न को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं करना चाहिए।
- (ii) याचिकाकर्ता संबंध वस्तुओं के सभी ग्रेडों का उत्पादन नहीं करते और कुछ आवेदक/समर्थक जैसे जे. सी. टी. सेंचुरी एंका और सालासर भी नायलॉन यार्न के विशिष्ट समान यार्न का आयात कर रहे हैं।
- (iii) कुछ याचिकाकर्ता/समर्थकों द्वारा विशिष्ट यार्नों का आयात भारत में ऐसे यार्न की अनुपलब्धता पर प्रकाश डाला गया है। ऐसे उत्पादों को अनिवार्य रूप से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से हटा देना चाहिए।
- (iv) घरेलू उद्योग नायलॉन 6 और 66 पीओवाई – 35 डी से 126 डी में 10 एफ से 12 एफ तक की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं है।

### **ख. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

9. वर्तमान जांच में शामिल विचाराधीन उत्पाद नायलॉन का सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है जिसे पॉलीएमाइड यार्न के रूप में भी जाना जाता है (नायलॉन फिलामेंट यार्न के रूप में भी वर्णित और संबद्ध वस्तुओं के रूप में भी संदर्भित)। नायलॉन फिलामेंट यार्न एक ऑर्गेनिक फिलामेंट के पॉलीमेराइजेशन द्वारा उत्पादित एक सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है।

10. विचाराधीन उत्पाद में सिलाई के धागों के अतिरिक्त, नायलॉन या पोलिएमिड्स के सभी प्रकार के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न शामिल हैं: जैसे फ्लैट यार्न – ट्विस्टिड और/ या अनट्विस्टिड, फुली ड्राँन यार्न (एफडीवाई) स्पिन ड्राँन यार्न (एसडीवाई), फुली ओरिएंटेड यार्न (एफओवाई) हाई ओरिएंटेड यार्न (एचओवाई) पार्सली ओरिएंटेड यार्न (पीओवाई) टैक्चर्ड यार्न-ट्विस्टिड और/या अन ट्विस्टिड और डाइड यार्न, एकल, दोहरा, विभिन्न, फोल्डिड या केबल्ड सीमा शुल्क उप-शीर्ष सं. 5402 के तहत अध्याय 54 के तहत वर्गीकृत करने योग्य है किंतु इसमें नायलॉन या अन्य पॉलीएमाइड के उच्च डेन्सिटी यार्न शामिल नहीं है।

11. संबद्ध वस्तुओं को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमा शुल्क उप-शीर्ष संख्या 5402 के अंतर्गत शीर्ष अध्याय-54 के तहत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से संबद्ध जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

12. वर्तमान जांच के एक निर्णायक समीक्षा होने के कारण और जैसा कि प्राधिकारी द्वारा पहले सिफारिश की गई थी, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क प्रवृत्त होने के कारण प्राधिकारी ने निर्णय किया है कि वर्तमान जांच में पीयूसी का क्षेत्र वही रहेगा जैसा कि मूल और उत्तरवर्ती समीक्षा जांच में था।

12. जहां तक इस दावे का संबंध है कि घरेलू उद्योग द्वारा कुछ विशिष्ट प्रकार के यार्न का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, प्राधिकारी ने टिप्पणी की है कि इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई समर्थक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और इसलिए इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

13. जहां तक इस दावे का संबंध है कि ऐसे कई किस्म के यार्न हैं जिनका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई समर्थक साक्ष्य नहीं दिया गया है और इसीलिए यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा रहा है।

14. समान वस्तु के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था की गई है:-

*“समान वस्तु” से तात्पर्य ऐसी वस्तु से है जो भारत में पाटित की जा रही जांचाधीन वस्तु से सभी प्रकार से समान है या एक जैसी है या ऐसी वस्तु की अनुपस्थिति में कोई अन्य वस्तु जो सभी पहलुओं में समान नहीं है, जांचाधीन वस्तुओं से गहन रूप से समान विशेषताएं रखती हैं।*

15. रिकार्ड पर दर्ज सूचना पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद में और भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं विशेषताओं के रूप में संबंध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं से तुलनीय है जैसे भौतिक और रसायनिक विशेषताएं विशेषताएं, कार्य और प्रयोग, उत्पाद संबंधी विशेष विवरण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से दोनों एक दूसरे के प्रतिस्थापनीय हैं। प्रयोक्ता दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं।

16. इसलिए प्राधिकारी ने माना है कि ए.डी. नियमावली के अनुसरण में आवेदक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, संबद्ध देशों से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

## ग. घरेलू उद्योग का कार्यक्षेत्र और मत

### ग. 1. घरेलू उद्योग के विचार

17. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित आवेदन किए गए हैं:-

i. विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों के रूप में मै. जे सी टी लि., मै. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स केमिकलक्स लि. (जीएसएफसी), मै. गुजरात पोलीफिल्मस प्रा.लि. (जी पी पी एल), मै. प्रफुल्ल ओवरसीज प्रा.लि. और मै. ए वाई एम सिनटैक्स लि. द्वारा याचिका दायर की गई है और सालासर पॉलीटेक्स, जेपीबी फाइबर (ईगल ग्रुप), गुप्ता सिंथेटिक्स लि., ओरिलॉन इंडिया प्रा. लि. और सेंचुरी एंका लि. ने समर्थन किया है।

ii. याचिकाकर्ताओं का उत्पादन भारतीय उत्पादन का प्रमुख समानुपातक है और इसलिए याचिकाकर्ताओं को नियमावली के अर्थों के भीतर “घरेलू उत्पादन” माना जाना चाहिए।

iii. ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि घरेलू उद्योगों के प्रत्येक संघटक को विचाराधीन उत्पाद के प्रत्येक और सभी प्रकारों को उत्पादित करना चाहिए। प्रत्येक उत्पादक के लिए उत्पाद के प्रत्येक प्रकार पर ध्यान केंद्रित करने की कोई जरूरत नहीं है।

### ग.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

18. इस संबंध में निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:-

i. याचिकाकर्ताओं में कुछ ऐसे उत्पादक शामिल हैं जो नायलॉन फिलामेंट यार्न के कुछ ग्रेड/ प्रकारों के आयातक हैं और “घरेलू उद्योग” के क्षेत्र में उन्हें सम्मिलित किए जाने पर पुनःविचार किए जाने की जरूरत है। याचिकाकर्ता ने “समर्थकों” के रूप में केवल चार अन्य कंपनियों – सालासर पॉलीटेक्स, जेपीबी फाइबर (ईगल ग्रुप), गुप्ता सिंथेटिक्स लि., और सेंचुरी एंका लि. को शामिल किया है। अद्यतन याचिका में एक अन्य समर्थक – मै. ओरिलॉन इंडिया को “शामिल” किया गया प्रतीत होता है। इस संबंध में कोई समर्थन पत्र नहीं जोड़ा गया है।

ii. सभी उत्पादकों और समर्थकों द्वारा अपना क्षति आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहिए और इस पर उद्योगवार क्षति आकलन पर विचार किया जाना चाहिए।

### ग. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच

19. आवेदक मै. जेसीटी लि., मै. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स केमिकलक्स लि. (जीएसएफसी), मै. गुजरात पोली फिल्मस प्रा.लि. (जी पी पी एल), मै. प्रफुल्ल ओवर सीज प्रा.लि. और मै. ए वाई एम सिनटैक्स लि. द्वारा दायर किया गया है और इसका सालासर पॉलीटैक्स, जेपीवी फाइबर (ईगल ग्रुप), गुप्ता सिंथेटिक्स लि., ओरिलॉन इंडिया प्रा. लि. और सेंचुरी एंका लि. द्वारा समर्थन किया गया है। आवेदकों और समर्थकों के अतिरिक्त संबद्ध वस्तुओं का कोई अन्य उत्पादक नहीं है।

20. आवेदन मै. जे सी टी लि., मै. गुजरात पोली फिल्मस प्रा. लि., मै. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स केमिकलक्स लि., मै. प्रफुल्ल ओवर सीज प्रा.लि. और मै. ए वाई एम सिनटैक्स लि. (पूर्व में वेलस्पन सिंटेक्स के रूप में ज्ञात) द्वारा दायर किया गया है। उत्पाद के पांच अन्य भारतीय उत्पादक हैं अर्थात् सालासर, जेपीवी फाइबर, गुप्ता सिंथेटिक्स लि., सेंचुरी एंका और ओरिलॉन इंडिया प्रा.लि. सभी अन्य उत्पादकों ने आवेदन का समर्थन किया है। याचिकाकर्ताओं ने न तो संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है न ही वे संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक या निर्यातक से संबंधित हैं, मै. जेसीटी लि. और मै. ए वाई एम सिंटेक्स के अतिरिक्त, जिन्होंने संबद्ध देशों से निम्न मात्रा में विचाराधीन उत्पाद (क्रमशः लगभग 148 मी.टन और 117 मी.टन) का आयात किया है। उनके आयात उनके अपने स्वयं के उत्पादन साथ ही कुल भारतीय उत्पादन का नगण्य भाग है इसलिए उन्हें पात्र घरेलू उत्पादक माना गया है। इसके अतिरिक्त, आवेदकों द्वारा किया गया उत्पादन समान उत्पाद के भारतीय उत्पादन का “प्रमुख अनुपात” स्थापित करता है। इसलिए यह निर्धारित किया गया है कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा और उनकी ओर से दायर किया गया है और आवेदन ए डी नियमावली के नियम 5 के तहत “स्थायी” की अनिवार्यता को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, आवेदक ए डी नियमावली के नियम व शर्तों में “घरेलू उद्योग” है।

### घ. विविध निवेदन

#### घ. 1. घरेलू उद्योग के विचार :-

21. घरेलू उद्योगद्वारा निम्नलिखित विविध निवेदन किए गए हैं :

i. वर्तमान एडीडी के समापन से काफी पहले, दिनांक जनवरी, 2017 की अधिसूचना के अनुसार जांच आरंभ की गई थी। धारा 9 क (5) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी पर एक मात्र बाध्यता है कि निर्णायक समीक्षा को ए डी डी की समाप्ति से पूर्व आरंभ किया जाना चाहिए जो कि वर्तमान मामले में किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा केवल जहां जरूरी था और वहां मार्ग निर्देशों के अंतर्गत गोपनीयता का दावा किया गया है, जैसा कि संगत कानूनों द्वारा स्थापित किया गया है। जहां तक रैप निर्दिष्ट के लिए एन एफ वाई 170/24 और 280/14 पर मांगी गई छूट का संबंध है, यह स्वीकार किया गया है कि एन एफ वाई 170/24 और 280/14 शुल्क की वैचमार्क कीमत प्राप्त कर रहे हैं। जहां तक ए डी ए के अनुच्छेद 5.3 के साथ असंगतता का प्रश्न है, यह नोट किया जाना चाहिए कि निर्णायक समीक्षा के मामले में नियम 5 और अनुच्छेद 5.3 प्रयोज्य नहीं है।

ii. यह पाटनरोधी कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि मांग आपूर्ति अंतर पाटन का औचित्य सिद्ध नहीं करता, ए डी डी का अधिरोपण आयातों को नहीं रोकता।

#### घ. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के मत:

22. इस संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध निवेदन किए गए हैं:

- i. मूल सीमा शुल्क अधिसूचना के समाप्त होने के पश्चात शुल्क का विस्तार नहीं किया जा सकता। निर्णायक समीक्षा के अंतरिम-काल में ए डी शुल्क का विस्तार गैर कानूनी रूप से किया गया है। अधिसूचना 19 तारीख को जारी की गई है जो मूल शुल्कों की समाप्ति के पश्चात है और इन्हें पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
- ii. अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्माण और निर्यात मूल्य त्रुटिपूर्ण है।
- iii. अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। सामान्य मूल्य का निर्धारण और निर्यात मूल्य त्रुटिपूर्ण है। याचिकाकर्ता की पी सी एन वार परिकलन और पश्च-पी ओ वाई सूचना की कमी की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
- iv. याचिका में साक्ष्य की कमी है और ए डी ए के अनुच्छेद 5.3 के असंगत है। कुल बिक्री कुल घरेलू उत्पादन से अधिक है, यह संगणना में त्रुटि को दर्शाता है। और इसने लगभग 96% क्षमता उपयोग भी प्राप्त किया है।
- v. याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले में कुछ निर्यातकों द्वारा असहयोग का आरोप लगाया है। तथापि, यह निवेदन गलत प्रतीत होता है क्योंकि वास्तव में पी टी सुसिलिय इंडाह सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज ने वर्तमान जांच में भाग लिया है और उनका प्राधिकारी द्वारा सत्यापन भी किया गया है।

- vi. याचिकाकर्ताओं के इस दावे का आधार कि फोरमोसा पहले ताइवान से पाटन में संलग्न था और अब इसने प्रचालनों को वियतनाम स्थानांतरित कर दिया है, तर्क को गलत दर्शाता है। फोरमोसा ने कभी भी ताइवान से जांच में भाग नहीं लिया था और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि क्या फोरमोसा कभी अपनी ताइवानी यूनिट से भारत के साथ व्यापार में संलग्न था। संपूर्ण तर्क विश्वास पर आधारित है और इससे “पाटन स्रोत के स्थानांतरण” का वास्तविक जोखिम स्थापित नहीं होता। पाटन के स्रोत का “स्थानांतरण” जैसा कि दावा किया गया है, वर्तमान शुल्कों के निवारण के दावे से अधिक नहीं है।
- vii. शुल्क से छूट वार्प निटिंग के लिए एन एफ वाई 170/24 और 280/14 पर दिया जाना चाहिए क्योंकि इसे हुक और पाश टेप फास्टर के लिए प्रयुक्त समान ग्रेड को दिया गया है।

### **घ. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

23. विविध हितबद्ध पक्षकारों ने पाटन निर्धारण की कार्य प्रणालियों और घरेलू उद्योग के क्षति संबंधी दावों सहित, वर्तमान जांच के संबंध में विभिन्न मुद्दे उठाए हैं। जहां, पाटन और क्षति निर्धारण से संबंधित मुद्दों का उचित स्थानों पर उल्लेख किया गया है, जांच के प्रति पक्षकारों द्वारा उठाए गए सामान्य मुद्दों की जांच की गई है और उनको संबोधित किया गया है जैसी कि नीचे व्यवस्था की गई है-

- i. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि मूल सीमा शुल्क अधिसूचना की समाप्ति के पश्चात् शुल्क का विस्तार नहीं किया जा सकता, यह नोट किया गया है कि प्राधिकारी ने पाटन रोधी शुल्कों की समाप्ति से पूर्व ही जांच को भली-भांति आरंभ कर दिया था, जैसा कि कानून के तहत यथा अपेक्षित है।
- ii. जहां तक इस दावे का संबंध है कि घरेलू उद्योग वार्प उद्योग की मांग को पूरा नहीं कर सकता, यह नोट किया गया है दावे की पुष्टि नहीं की गई है और किसी भी तरह से पाटन रोधी शुल्क का अधिरोपण आयातों को नहीं रोक सकता। कुल मिला कर यह पाटन आयातों के साथ संबद्ध व्यापार-विकृति प्रभाव को समाप्त कर सकता है।
- iii. जहां तक याचिकाकर्ता के दावे के प्रभाव का संबंध है कि फोरमोसा पहले, ताइवान से पाटन में संलग्न था और अब इसने प्रचालनों को वियतनाम स्थानांतरित कर दिया है, प्राधिकारी ने नोट किया है कि संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है और वास्तव में वियतनाम से उल्लेखनीय मात्रा में घरेलू बाजार में आयातों का प्रभाव आरंभ हो गया है इसलिए पाटन में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
- iv. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिका में साक्ष्य की कमी है और यह ए डी ए के अनुच्छेद 5.3 के असंगत है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कि घरेलू उद्योग ने पूरी तरह से प्रमाणित आवेदन दायर किया है और प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के पश्चात् ही जांच आरंभ की थी।
- v. जहां तक अत्यधिक गोपनीयता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई है। संतोषजनक पाए जाने पर, प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया, जहां भी जरूरत थी और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, जहां भी संभव था, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना के पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। प्राधिकारी ने पब्लिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराया है।

### **ड. पाटन मर्जिन बाजार अर्थव्यवस्था उपचार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और निर्धारण**

#### **ड. 1. घरेलू उद्योग के विचार**

24. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार निवेदन किया है:

- i. परिग्रहण प्रोटोकॉल के उपबंधों में से एक 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को नीचे दिए गए कारणों से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में प्रचालन कर रहे उत्पादकों के रूप में चीनी उत्पादकों के संबंध में विचार करते हुए वर्तमान जांच पर आगे कार्यवाई करनी चाहिए।
- ii. वर्तमान मामले में प्राधिकारी द्वारा विचारित जांच की अवधि अप्रैल, 2015 से सितंबर, 2016 (18 महीने) है।
- iii. पी ओ आई निर्धारित करने का प्रयोजन ऐसी अवधि पर विचार करना है जहां क्षति करने वाले पाटन की विद्यमानता का दावा तथा उसे स्थापित किया जाता है।



- iv. चीनी उत्पादकों को इस कारण गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियों के रूप में माने जाने की आवश्यकता है कि चीन में लागतें और कीमतें बाजार दबावों को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं करतीं। अनुबंध - I का पैरा-8 उन पैरामीटरों को विनिर्दिष्ट करता है जिन पर बाजार अर्थव्यवस्था प्रास्थिति प्रदान किए जाने के लिए विचार किया जाना चाहिए।
- v. चूंकि, दिसंबर, 2016 तक चीनी कंपनियों को अनुबंध - I के पैरा-8 में उल्लिखित कारणों से बाजार अर्थव्यवस्था प्रास्थिति प्रदान करने से मना किया गया है, याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि चीनी उत्पादकों को ऐसे समय तक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था कंपनियों के रूप में माने जाने की जरूरत है जब तक जांच अवधि में परिग्रहण प्रोटोकॉल में विनिर्दिष्ट अवधि को शामिल किया जाता है।
- vi. चीनी उत्पादकों को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वातावरण के अंतर्गत प्रचालन कर रही कंपनियों के रूप में माने जाने की जरूरत है और प्राधिकारी अनुबंध - I के पैरा-7 के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं।
- vii. सामान्य मूल्य को इस कारण तीसरे देश की उचित बाजार अर्थव्यवस्था में समान वस्तु कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता ने भारत में भली-भांति समायोजित उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किए जाने का दावा किया है।
- viii. चीन से पाटन मार्जिन न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि उल्लेखनीय भी है इसलिए यह भारत में विचाराधीन उत्पाद के महत्वपूर्ण पाटन की विद्यमानता को स्थापित करता है। प्रवृत्त पाटन रोधी शुल्क के बावजूद, वर्तमान पूर्ण क्षति अवधि के दौरान महत्वपूर्ण बनी रही हैं।
- ix. चीनी उत्पादकों के पास उपलब्ध उत्पादन क्षमताओं और उनके उच्च निर्यात प्रचालनों को ध्यान में रखते हुए, न केवल पाटन जारी रहेगा बल्कि पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति की दशा में और अधिक गहन होगा।
- x. चीनी ताइपेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कोरिया पी.आर. के लिए भी याचिकाकर्ताओं ने भली-भांति समायोजित, निर्यातक देशों में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है।

## **च. 2 हितबद्ध पक्षकारों के विचार**

25. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं-

- याचिकाकर्ता सामान्य मूल्य और सर्वोत्तम अनुमानों के स्रोत के लिए परिकलन के आधार को प्रकट करने में असफल रहे हैं। याचिकाकर्ता यह उल्लेख करने में भी असफल रहे हैं कि किन कारकों को “संगत” माना गया है। याचिकाकर्ता ने साक्ष्य के जरिए निर्यात कीमत के लिए समायोजनों को स्थापित करने के उत्तरदायी की उपेक्षा की है। यह पूर्व धारणा कि शुल्क की वापसी जोखिम उत्पन्न करेगी, याचिकाकर्ताओं के आंकड़ों द्वारा प्रमाणित नहीं होती, अथवा इंडोनेशिया से आयातों से उत्पन्न नहीं होता।
- याचिकाकर्ताओं के दावे का आधार कि फोरमोसा पहले ताइवान से पाटन में संलग्न था और अब प्रचालन वियतनाम स्थानांतरित कर दिए हैं, तर्क को गलत साबित करता है। फोरमोसा ने ताइवान से जांच में कभी भी भाग नहीं लिया और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि क्या फोरमोसा कभी अपनी ताइवानी युनिट से भारत के साथ व्यापार में संलग्न था। संपूर्ण तर्क मात्र एक विश्वास है और “पाटन स्रोत के स्थानांतरण” के किसी वास्तविक जोखिम को स्थापित नहीं करता।

## **ड. 3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

### **ड.3.1 बाजार अर्थव्यवस्था दावों की जांच**

26. जांच प्रारंभ होने के स्तर पर, याचिकाकर्ताओं ने चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानने की पूर्वधारणा के साथ कार्रवाई आरंभ की। जांच प्रारंभ होने पर, प्राधिकारी ने चीन में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच आरंभ होने के नोटिस का प्रत्युत्तर देने और इस निर्धारण के संगत सूचना उपलब्ध कराने की सलाह दी कि क्या सामान्य मूल्य निर्धारण के प्रयोजनार्थ उनके आंकड़ों/सूचना को अपनाया जा सकता था। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली की प्रतियां भेजी थी। हालांकि, किसी भी चीनी उत्पादक/निर्यातक ने कोई उत्तर दायर नहीं किया है।

27. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के किसी भी उत्पादक और निर्यातक ने निर्यातकों की प्रश्नावली के उत्तर और अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। असहयोग के कारण, प्राधिकारी उनकी प्रश्नावली प्रत्युत्तर के आधार पर चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में असमर्थ रहा है।

28. इसके अतिरिक्त, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने, घरेलू उद्योग सहित, चीन में लागत या कीमत पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी को कोई महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध नहीं कराया है। इसलिए प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(8) की शर्तों में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर चीन जन.गण. के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

### **ड. 3.2 चीन जन.गण. में उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण**

29. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, भारत में चीन जन.गण. से आयातित संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य को घरेलू उद्योग के लिए अनुमत स्तरों पर कच्ची सामग्री और युटिलिटीज, परिवर्तन लागत, ब्याज, एसजीए आदि के लिए घरेलू उद्योग के इष्टतम खपत मानदंडों पर, उन पर उचित लाभ सहित, विचार करते हुए निर्मित किया गया है। प्रत्येक पी सी एन के लिए पृथक सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

### **ड. 3.3 चीन जन.गण. के लिए नियति कीमत का निर्धारण**

30. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. से किसी भी निर्यातक ने प्राधिकारी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई है जिसका प्रयोग निर्यात कीमत और व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए प्रयोग किया जा सकता। इसलिए, प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के सौदावार आंकड़ों के आधार पर चीन से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत पर पहुंचने के लिए समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा कमीशन, बैंक प्रभारों, पत्तन व्यय और अंतर्देशीय माल-भाड़ा प्रभारों के कारण निर्यात कीमत समायोजित किया गया है। तदनुसार, चीन जन.गण. से निर्यातों के लिए कारखानागत स्तर पर निवल निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन सारणी में दर्शाए गए अनुसार है:-

विवरण	यूओएम	चीन जन.गण.
निवल निर्यात कीमत टन.मी./	अम.डॉ./मी.ट.	***
सामान्य मूल्य	अम.डॉ./मी.ट.	***
पाटन मार्जिन	अम.डॉ./मी.ट.	***
पाटन मार्जिन	%	20-30 %

### **ड. 3.4 इंडोनेशिया के लिए सामान्य मूल्य निर्धारण**

31. प्राधिकारी द्वारा ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को उन्हें निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सूचना उपलब्ध कराने की सलाह देते हुए प्रश्नावली भेजी गई है। इंडोनेशिया से निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली का उत्तर दायर किया गया।

क. पीटी इंडाची प्राइमा, इंडोनेशिया

ख. सुलिनदाफिन, इंडोनेशिया

32. इंडोनेशिया में उत्पादकों/निर्यातकों से प्राप्त प्रश्नावली उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रत्युत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन को उनके प्रश्नावली उत्तर के आधार पर निर्धारित किया गया है।

33. निर्यातक प्रश्नावली (ई क्यू) उत्तर से, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. पी टी इंडाची प्राइमा, इंडोनेशिया भारत को संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक/निर्यातक है। निर्यातक द्वारा दायर और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित की गई सूचना के अनुसार, जांच की अवधि के दौरान पी टी इंडाची प्राइमा ने घरेलू बाजार में \*\*\* मी.टन संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की। प्राधिकारी ने प्रत्येक पी सी एन के लिए कंपनी के उत्पादन की लागत पर विचार किया है और निर्धारित किया कि क्या घरेलू बाजार में बिक्री मूल्य व्यवहार्य और प्रतिनिधिकारी या उन सभी मामलों में जहां पी सी एन के लिए 80% से अधिक बिक्री लाभप्रद थी, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में सारी बिक्रियों पर विचार किया गया है। उन सभी मामलों में, जहां, पी सी एन के लिए

80% से कम बिक्री लाभप्रद थी, सामान्य मूल्य के निर्धारण में केवल लाभ देने वाली बिक्रियों, करों, कमीशन, अंतर्देशीय माल भाड़ा और क्रेडिट लागत के कारण कीमत समायोजनों का दावा किया गया है और उचित सत्यापन के बाद उन्हें स्वीकृति दी गई है। पी सी एन वार सामान्य मूल्य को पी टी इंडाची प्राइमा, इंडोनेशिया के लिए निर्धारित किया गया है। भारांशित औसत सामान्य मूल्य को \*\*\* अमरीकी डॉलर प्रति मी.टन के रूप में निर्धारित किया गया है।

34. मै. सुलइंदाफिन द्वारा दायर निर्यातक प्रश्नावली उत्तर में, पी ओ आई के दौरान भारत को निर्यात बिक्री के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। तदनुसार, सुलइंदाफिन, इंडोनेशिया को कोई व्यक्तिगत मार्जिन या उपचार नहीं दिया जा सकता।

### **ड. 3.5 पी टी इंडाची प्राइमा, इंडोनेशिया के लिए निर्यात कीमत**

35. पी टी इंडाची प्राइमा के लिए निर्यात कीमत को निर्यातक द्वारा दायर और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित प्रश्नावली उत्तर के आधार पर निर्धारित किया गया है। उत्पादक/निर्यातक ने \*\*\* अमरीकी डॉलर/मी.टन की भारांशित औसत निवल निर्यात कीमत पर पी ओ आई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं के \*\*\* मी.टन का निर्यात किया है। एक्स फैक्ट्री स्तर पर जिसे सत्यापित किया गया है और एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत निर्धारित करने, निवल निर्यात कीमत को निर्धारित करने के लिए क्रेडिट लागत, अंतर्देशीय माल भाड़ा, कमीशन, सीमा-शुल्क निपटान प्रभार, समुद्री माल भाड़ा और बैंक प्रभारों के कारण समायोजनों पर विचार किया गया है। भारत को निर्यातित प्रत्येक पी सी एन के लिए पृथक निर्यात कीमत निर्धारित की गई है।

### **ड. 3.6 इंडोनेशिया में असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत**

36. इंडोनेशिया के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य को निर्धारित किया गया है, जबकि निर्यात मूल्य के संबंध में सहयोगी निर्यातक के भारत को निर्यात संबंधी आंकड़ों के आधार पर विचार किया गया है। इसके आधार पर, पाटन मार्जिन संगत सारणी में दर्शाया गया है।

### **ड. 3.7 मलेशिया के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण**

37. प्राधिकारी ने ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को उन्हें निर्धारित प्रपत्र और तरीके में सूचना उपलब्ध कराने की सलाह देते हुए प्रश्नावली भेजी है। मलेशिया से निम्नलिखित उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रश्नावली का उत्तर दायर किया गया:

क. मै. रेक्रॉन (मलेशिया) एस डी एन बी एच डी, मलेशिया

38. मै. रेक्रॉन, मलेशिया द्वारा निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दायर किया गया है। तथापि, यह देखा गया है कि उत्तर प्रस्तुत करने वाले निर्यातक/उत्पादक द्वारा उनके घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तुओं की घरेलू बिक्री भारत को निर्यातित मात्रा के 5% से कम है और इस प्रकार अपनी घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिनिधि नहीं है और अतः व्यापार परीक्षा मानदंड की सामान्य प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए, निर्यातक के उत्पादन की लागत और 5% की उचित लाभ दर के आधार पर उत्तर देने वाले निर्यातक/उत्पादक के लिए पीसीएनवार सामान्य मूल्य को निर्धारित किया गया है।

### **ड. 3.8 रेक्रॉन (मलेशिया) एस डी एन बी एच डी, मलेशिया के लिए निर्यात कीमत**

39. निर्यातक द्वारा दायर और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित प्रश्नावली उत्तर के आधार पर निर्यात कीमत को निर्धारित किया गया है। उत्पादक/निर्यातक ने \*\*\* अमरीकी डॉलर/मी.टन के भारांशित औसत निवल निर्यात कीमत पर पी ओ आई के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का \*\*\* मी.टन निर्यात किया है। एक्स फैक्ट्री स्तर पर, जिसे एक्स फैक्ट्री निर्यात कीमत को निर्धारित करने के लिए सत्यापित और अनुमोदित किया गया है, एक्स फैक्ट्री स्तर पर निवल निर्यात कीमत को निर्धारित करने के लिए विदेशी माल भाड़ा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, कमीशन, सीमा शुल्क प्रबंध प्रभार, कंटेनर सील प्रभार, व्याज कीमत, बीमा और बैंक प्रभारों के कारण समायोजनों पर विचार किया गया है। भारत को निर्यातित प्रत्येक पी सी एन के लिए पृथक निर्यात कीमत निर्धारित की गई है।

### **ड. 3.9 मलेशिया में असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत**

40. मलेशिया के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य को निर्धारित किया गया है जबकि निर्यात मूल्य को भारत को निर्यातों पर सहयोगी निर्यातक के आंकड़ों के आधार पर विचारित किया गया है। इसके आधार पर, पाटन मार्जिन को प्रासंगिक सारणी में इंगित किए गए अनुसार मूल्यांकित किया गया है।

**ड. 3.10 ताइवान, थाईलैंड और कोरिया के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण****ताइवान, थाईलैंड और कोरिया के लिए सामान्य मूल्य**

41. चूंकि, ताइवान, थाईलैंड और कोरिया से किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने प्रत्युत्तर नहीं दिया है, प्राधिकारी ने उचित लाभ सहित घरेलू उद्योग के लिए अनुमत स्तरों पर कच्ची सामग्री और उपयोगिता, परिवर्तन लागत, ब्याज, एस जी ए आदि के लिए घरेलू उद्योग के इष्टतम खपत मानदंडों पर विचार करते हुए भारत में उत्पादन की लागत को अपनाते हुए नियम 6(8) के अनुसरण में सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया है। प्रत्येक पी सी एन के लिए पृथक सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है।

**ड. 3.11 ताइवान, थाईलैंड और कोरिया में निर्यात कीमत**

42. चूंकि ताइवान, थाईलैंड और कोरिया से किसी भी उत्पादकों/निर्यातकों ने सहयोग नहीं किया है, अतः सी आई एफ कीमत को निर्धारित करने के लिए डी जी सी आई एंड एस के आयात आंकड़ों को अपनाया गया है। कारखानागत निर्यात कीमत का मूल्यांकन करने के लिए, समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, अंतर्देशीय माल भाड़ा और पत्तन व्यय के लिए समायोजन किए गए हैं। आयातों के पहुंच मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन योग्य मूल्य पर आधारभूत सीमा शुल्क और उपकर लागू किए गए हैं जो 1% पहुंच प्रभारों के साथ आयातों के सी आई एफ मूल्य के समकक्ष है। भारत में प्रत्येक किस्म के पी सी एन के लिए पृथक भारत औसत निर्यात कीमत निर्धारित की गई है।

**ड. 3.12 पाटन मार्जिन**

43. संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन को संबद्ध वस्तुओं के लिए कारखानागत स्तर पर पी सी एन वार सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत की तुलना द्वारा निर्धारित किया गया है। नीचे दी गई सारणी सभी संबद्ध देशों के लिए भारांशित औसत पाटन मार्जिनों को दर्शाती है।

**सारणी**

देश	उत्पादकनिर्यातक/	डी एम अमरीकी डॉलरएमटी/	डीएम %	रेंज में डीएम %
चीन जन.गण.	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	20-30
इंडोनेशिया	मै. पी टी इंडाची प्राइमा	***	***	65-75
	अन्य	***	***	115-125
कोरिया	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	20-30
मलेशिया	मै. रेक्रॉन	***	***	10-20
	अन्य	***	***	45-55
ताइवान	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	20-30
थाईलैंड	सभी उत्पादक/निर्यातक	***	***	20-30

44. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन प्रत्येक संबद्ध देश से किए गए निर्यातों के संबंध में नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक हैं।

**च. क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण****च. 1. घरेलू उद्योग का मत**

45. जहां तक क्षति और कारणात्मक संबंध का संबंध है, घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार निवेदन किए हैं :-

i. संबद्ध वस्तुओं की मांग/प्रत्यक्ष खपत में पी ओ आई सहित क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। हालांकि, संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है किंतु भारत में उत्पादन/खपत के संबंध में और कुल रूप में, दोनों में, पाटनरोधी शुल्क के बावजूद आयात महत्वपूर्ण बने रहे हैं।

- ii. संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति अवधि में लगातार वृद्धि हुई है। पहले उपलब्ध कराई गई आयात मात्रा और बाजार हिस्से से संबंधित सूचना दर्शाती है कि क्षति अवधि में आयातों में गिरावट आई है। बाजार हिस्से ने आयातों की मात्रा की प्रवृत्तियों का अनुसरण किया है।
- iii. आयात घरेलू कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती कर रहे हैं। क्षति अवधि में कटौती की मात्रा बड़ी है। कीमत दमन/ह्रास के संबंध में, क्षति अवधि के दौरान उत्पादन की लागत में गिरावट की तुलना में, बिक्री कीमत में गिरावट अधिक होने के कारण उत्पादन की लागत और बिक्री कीमत में गिरावट आई है। बिक्री कीमत लगातार उत्पादन की लागत के स्तर से नीचे बनी रही है। आयातों की पहुंच कीमत बिक्री कीमत और उत्पादन की लागत के स्तर से काफी कम है।
- iv. आयातों की पहुंच कीमत और क्षतिरहित कीमत के बीच तुलना दर्शाता है कि जांच की अवधि में आयातों की पहुंच कीमत क्षतिरहित कीमत से काफी कम रही है जिसके परिणामस्वरूप कीमत से कम कीमत पर बिक्री हुई।
- v. घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी वृद्धि हुई है। माल सूची का स्तर समाना रेंज में बना रहा है और महत्वपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं ने मात्रा पैरामीटरों के कारण क्षति का दावा नहीं किया है।
- vi. घरेलू उद्योग सामना की जा रही वित्तीय हानियों ने पूरी क्षति अवधि के दौरान कमी की प्रवृत्ति दर्शाई है, हालांकि हानियां उल्लेखनीय बनी रही हैं। विचाराधीन उत्पाद या तो मोनो फिलामेंट या मल्टी फिलामेंट हो सकते हैं। मोनो फिलामेंट यार्न में, चूंकि संबद्ध देशों से होने वाले उत्पाद के आयात की मात्रा कम है, घरेलू उद्योग ने लाभ अर्जित किया है और वर्षों के साथ-साथ लाभों में वृद्धि हुई है। मल्टी फिलामेंट में, चूंकि संबद्ध देश, साथ ही अन्य देशों (जिस के विरुद्ध जांच की जा रही है) से भी विचाराधीन उत्पाद पाटित किया जा रहा है, घरेलू उद्योग अत्यधिक वित्तीय हानियों का सामना कर रहा है।
- vii. कानून के तहत मल्टी फिलामेंट यार्न और मोनो फिलामेंट यार्न के लिए पृथक क्षति विश्लेषण गैर-कानूनी है। क्षति मार्जिन विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु के लिए होना चाहिए।
- viii. घरेलू उद्योग मल्टी फिलामेंट यार्न में उल्लेखनीय वित्तीय नकद हानियों का सामना कर रहा है जबकि मोनो-फिलामेंट में यह नकद लाभ अर्जित कर रहा है, जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि मल्टी फिलामेंट यार्न पर विपरीत प्रभाव पाटित आयातों के कारण है।
- ix. 2013-14 में निवेश पर आय ऋणात्मक थी और इसके बाद इसने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है। तथापि, आर ओ आई अभी भी भारत में बैंकों की ब्याज दर से अभी भी काफी कम है। घरेलू उद्योग ने मल्टी फिलामेंट में नियोजित पूंजी पर महत्वपूर्ण ऋणात्मक वापिसी का सामना किया है जबकि मोनो फिलामेंट ने नियोजित पूंजी पर सकारात्मक वापिसी अर्जित की है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मल्टी फिलामेंट पर विपरीत प्रभाव पाटित आयातों के कारण है।
- x. घरेलू उद्योग ने 2013-14 के पश्चात नकद लाभ अर्जित किया है किंतु ये लाभ घरेलू उद्योग को संपोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- xi. केवल 2014-15 और उसके बाद से ही आर ओ आई सकारात्मक बने किंतु अभी भी अगाध रूप से खराब स्तर पर बने हुए हैं। आर ओ आई भारत में बैंकों की ब्याज दर से भी काफी कम है।
- xii. मांग में डी आई का बाजार हिस्सा समान स्तर पर बना रहा है जबकि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।
- xiii. कर्मचारियों की संख्या और अदा की गई मजदूरी में गिरावट आई है। उत्पादन के सामंजस्य में क्षति अवधि के दौरान प्रतिदिन और प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई है।
- xiv. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण हैं। पाटन रोधी शुल्कों ने एक निवारक के रूप में कार्य किया है और भारत में वस्तुओं की तेजी से पाटित की जाने वाली वृहत मात्रा से संबद्ध देशों को रोकता है। हालांकि, संगत अवधि के दौरान भारत को जो भी मात्रा निर्यातित की गई है, वह पाटित और क्षतिकारक कीमत पर की गई है।
- xv. पाटन रोधी शुल्क के अधिरोपण के बावजूद और मध्यवर्ती समीक्षा में ऐसे शुल्क की मात्रा में तदनुरूपी वृद्धि और विगत में आयोजित निष्पक्ष समीक्षा में शुल्कों में विस्तार के बावजूद पाटित कीमतों पर संबद्ध उत्पाद का आयात जारी रहा। आयात मात्रा में गिरावट अन्य देशों से होने वाले अतिरिक्त पाटन के कारण आई है, जो इस समय जांचाधीन है।
- xvi. अधिनियम और नियमावली ऐसी किसी समय सीमा को निर्धारित नहीं करते जिसके पश्चात पाटन रोधी शुल्क का विस्तार नहीं किया जा सकता। कानूनी उपबंध स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पाटन रोधी शुल्क का समय-समय पर और विस्तार

किया जा सकता है यदि यह पाया जाए कि पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है। ऐसे भारतीय मामलों, जिनमें शुल्क को 15 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, का संदर्भ दिया गया है—एक्रेलिक फाइबर (थाईलैंड और कोरिया आर पी), एक्रिलोनीट्राइल बुटाडीन रबर (कोरिया आर पी), चीन से विटामिन सी हैं।

xvii. वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच को नई जांच समझने में भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। किसी निर्णायक समीक्षा जांच में न्यूनतम सीमा का कोई मापदंड नहीं है। यहां तक कि आयातों की निम्न मात्रा भी पाटन और क्षतिकारक कीमत पर आ रही हैं और उनकी कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही हैं।

xviii. पाटन और क्षतिकारक कीमतों पर आयातों का आना जारी है जो स्वयं में संबद्ध देशों से निर्यातकों के संभावित व्यवहार को दर्शाता है। विभिन्न कारक जैसे पाटन के स्रोत के स्थानांतरण की संभावना, निर्यातकों की प्रचुर उत्पादन क्षमता और विदेशी उत्पादकों का निर्यात निर्धारण, सभी पिछली जांचों में निर्धारित पाटन मार्जिन, भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता और घरेलू उद्योग की दोषपूर्णता पाटन और क्षति के जारी रहने की संभावना को दर्शाता है।

xix. यार्न की खराब गुणवत्ता के संदर्भ में दावों को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तुओं की बिक्री करने में सक्षम है और पाटन के कारण निम्न हो रही कीमतों की वजह से क्षति झेल रहे हैं।

xx. घरेलू उद्योग पाटन रोधी शुल्कों के अधिरोपण के बावजूद केवल मामूली लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। पाटन शुल्क की समाप्ति की स्थिति में आर एंड डी में नवीन परिवर्तन और निवेश वर्तमान परिदृश्य में संभव नहीं है जबतक कि घरेलू उद्योग की पाटन से सुरक्षा नहीं की जाती।

## च. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के मत

46. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं:

i. याचिकाकर्ताओं ने आयात डेटा के लिए आईबीआईएस डेटा का आश्रय लेने का दावा किया है। वे स्वयं में भ्रमित हैं क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा है कि वे आई बी आई एस डेटा पर निर्भर करेंगे क्योंकि डीजीसीआई एंड एस डेटा विश्वास योग्य नहीं हैं। इसके विपरीत, उन्होंने आई बी आई एस की बजाय डी जी सी आई एंड एस पर भरोसा कर अपने डेटा को अद्यतित किया है। लिखित निवेदन में याचिकाकर्ताओं ने दुबारा कहा है कि केवल आई बी आई एस डेटा का प्रयोग किया गया है।

ii. याचिकाकर्ताओं द्वारा किया गया क्षति आकलन समर्थकों के डेटा पर विचार किए बिना याचिकाकर्ताओं के डेटा पर आधारित है। वर्तमान मामले तथा समानांतर नई जांच में पी ओ आई की अवधि अक्टूबर, 2015 से सितंबर, 2016 (1 वर्ष) के बीच विस्तारित है। वर्तमान मामले में समान क्षति के उपचार को दोहराए जाने का जोखिम बहुत अधिक है।

iii. पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और कीमत में कटौती को ग्रेडवार निर्धारित किया गया है, किंतु इसका अन्य “पी सी एन” के तहत उल्लेख किया गया है, जिसका आधार स्पष्ट नहीं है।

iv. मल्टी फिलामेंट यार्न और मोनो फिलामेंट यार्न के लिए पृथक क्षति विश्लेषण की जरूरत है। निश्चित शुल्क रूप में पाटन रोधी शुल्क को मल्टी फिलामेंट यार्न के संबंध में एन एफ वाई मामले में लागू किया गया था किंतु बैच मार्क कीमत को मोनो फिलामेंट यार्न के संबंध में लागू किया गया था। इसे जारी रखा जाना चाहिए।

v. इंडोनेशिया से भारत में आयात ह्रासित कीमतों पर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। मल्टी फिलामेंट यार्न के संबंध में, इंडोनेशियाई आयात भारत में ह्रासित या न्यूनकारीकीमतों पर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। इंडोनेशिया से होनेवाले आयात मुख्य रूप से मोनो फिलामेंट यार्न के हैं जो सर्वसम्मति से याचिकाकर्ताओं को क्षति का कारण नहीं है।

vi. भारतीय उद्योग को लगातार क्षति का दावा गलत है। पी ओ आई के संबंध में याचिका दायर करने के समय कीमत ह्रास और न्यूनीकरण विद्यमान नहीं था किंतु लिखित निवेदन प्रस्तुत करते समय यह अचानक उभर कर सामने आ गया।

vii. याचिकाकर्ता किसी सतत क्षति या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की विद्यमानता को स्थापित करने में असफल रहा है। घरेलू उद्योग सबसे क्षति का सामना कर रहा है जब बड़ी हुई क्षमता के कारण ए डी डी लागू किए गए थे जिस कारण उच्च व्याज लागत और उच्च मूल्य ह्रास घटित हुआ।

viii. घरेलू उद्योग ने अन्य घरेलू उत्पादकों के साथ पारस्परिक प्रतिस्पर्धा में कमजोर निष्पादन दर्शाया है। ए डी डी समाप्त करने पर घरेलू उद्योग की प्रास्थिति में बदलाव नहीं होगा।

- ix. आंकड़ों की मुख्य विशेषताएं दर्शाती हैं कि संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा अब तक की सबसे निम्न है। संबद्ध देशों से आयात आधार वर्ष में किए गए आयातों की मात्रा की आधी है और पी ओ आई में इन में गिरावट आई है। अन्य देशों से आयातों में 228% तक की वृद्धि हुई है।
- x. आयातों में गिरावट की तुलना में भारतीय उत्पादकों के उत्पादन और खपत में वृद्धि हुई है। क्षति आकलन के लिए एक कारक के रूप में कीमत से कम कीमत पर बिक्री के संबंध में याचिकाकर्ता का दावा गलत है क्योंकि क्षति के विश्लेषण के लिए यह अनुमेय नहीं है।
- xi. यहां यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता एक विस्तृत हो रहे बाजार में 42% बाजार हिस्से को अनुरक्षित नहीं कर सका है क्योंकि अन्य भारतीय उत्पादकों साथ ही अन्य देशों से आयातों में भी वृद्धि हुई है।
- xii. याचिकाकर्ता के मानदंड सकारात्मक प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं और किसी भी क्षति को नहीं दर्शाते। उत्पादन, क्षमता और क्षमता उपयोगिता सभी में वृद्धि हो रही है। 2012-13 के बीच मालसूची में गिरावट आई है और उसके पश्चात यह लगातार स्थिर बनी रही है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मोनो फिलामेंट यार्न में लाभ प्राप्त किया गया है किंतु मल्टी फिलामेंट यार्न में महत्वपूर्ण नकद हानि हुई है। याचिकाकर्ताओं ने ब्याज और मूल्य ह्रास लागतों के संबंध में आंकड़ों पर रोक लगाई है कि पी वी आई टी (ब्याज और कर से पहले लाभ) उच्च है। और इस प्रकार, याचिकाकर्ता ह्रासकारी बिक्री कीमत के कारण हानियों का सामना नहीं कर रहे हैं। कथित पाटन के कारण कोई “क्षति” नहीं हुई है। मल्टी फिलामेंट यार्न के संबंध में बढ़ी हुई नियोजित पूंजी भी यह संकेत करती है कि ब्याज लागतें उच्च हैं। याचिकाकर्ताओं ने निम्न आर ओ आई के लिए पाटन आयातों को जिम्मेवार ठहराया है किंतु वास्तव में क्षति अवधि के दौरान उन्होंने अपनी क्षमता को बढ़ाया है और इस प्रकार नियोजित पूंजी में भी वृद्धि हुई है।
- xiii. लाभों, बाजार हिस्से, नकद लाभ और मालसूची पर लाभों के विपरीत प्रभाव से संबंधित निष्कर्ष आधारहीन है क्योंकि लाभों में वृद्धि हुई है जबकि हानियों में गिरावट आई है। बढ़ी हुई उत्पादन मात्रा की तुलना में मालसूची में गिरावट आई है।
- xiv. कर्मचारियों की संख्या, अदा की गई मजदूरी और प्रतिदिन एवं प्रति कर्मचारी उत्पादकता के प्रवृत्ति विश्लेषण के आधार पर कोई क्षति नहीं देखी गई है।
- xv. कुछ विशिष्ट देशों से आयात न्यूनतम अपेक्षित स्तर से कम है और इसलिए विश्लेषण में चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया को शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि सामूहिक रूप से वे 7% से कम हैं और वैयक्तिक रूप से 3% से कम हैं।
- xvi. घरेलू उद्योग द्वारा खराब गुणवत्ता वाली सामग्री के प्रयोग का परिणाम भारी हानि और खराब उत्पादन कार्यकुशलता है। यह उनके द्वारा पुरानी और अप्रचलित तकनीकों का प्रयोग करने के कारण भी है।
- xvii. इससे यह निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता कि वे वियतनाम और यूरोपीय संघ (ई.यू.) से पाटन के बुरे प्रभाव को झेल रहे हैं।

### **च. 3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

47. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों पर ध्यान दिया है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में क्षति के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों की जांच की है।
48. भारत में घरेलू उद्योग पर आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, प्राधिकारी ने उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संगत कारकों और आंकड़ों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, स्टॉक, लाभ प्रदत्ता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि, पर नियमावली के अनुबंध II(iv) के अनुसरण में विचार किया है।
49. पीसीएन पद्धति को उचित तुलना के लिए अपनाया जाने के बावजूद प्राधिकारी ने वर्तमान अभ्यास एवं एंटी डंपिंग नियमों के अनुसार समग्र आधार पर चोट विश्लेषण किया है।

#### **च. 3.1 पाटन आयातों का मात्रात्मक प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उसका प्रभाव**

##### **क. मांग और बाजार हिस्सा**

50. भारत में उत्पादन की कुल मांग या खपत, सभी स्रोतों से सभी भारतीय उत्पादकों और आयातों की घरेलू बिक्रियों का जोड़ है। इस प्रकार आकलित की गई मांग नीचे सारणी में दी गई है-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	वार्षिक रूप में पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
संबद्ध देशों से आयात	मी.टन	19,400	14,415	13,659	12,849
पृथक एडीडी जांच के तहत अन्य देशों से आयात	मी.टन	4,594	7,237	10,523	12,794
बाकी अन्य देशों से आयात	मी.टन	1,107	594	765	218
<b>मांग/खपत</b>	<b>मी.टन</b>	<b>68,275</b>	<b>75,459</b>	<b>90,088</b>	<b>1,05,145</b>
<b>मांग में बाजार हिस्सा</b>					
घरेलू उद्योगों की बिक्री	%	43.27%	49.49%	44.61%	42.19%
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	%	19.97%	21.03%	27.70%	33.21%
संबद्ध देशों से आयात	%	28.41%	19.10%	15.16%	12.22%
पृथक जांच के अंतर्गत अन्य देशों से आयात	%	6.73%	9.59%	11.68%	12.17%
अन्य देशों से आयात	%	1.62%	0.79%	0.85%	0.21%
<b>मांग/खपत</b>	<b>%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूरी क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। तथापि, मांग/खपत में संबद्ध देशों से आयातों के हिस्से में गिरावट आई है। मांग में घरेलू उद्योग के हिस्से में बहुत मामूली गिरावट दर्ज की गई है।

**ख. संबद्ध देशों की आयात मात्रा और हिस्सा**

52. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्या पाटित आयातों में कुल रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है :-

आयात मात्रा	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	वार्षिक पीओआई
संबद्ध देश	मी.टन	19,400	14,415	13,659	12,849
पृथक जांच के अंतर्गत अन्य देशों से आयात	मी.टन	4,594	7,237	10,523	12,794
अन्य देश	मी.टन	1,107	594	765	218
कुल आयात	मी.टन	25,101	22,247	24,946	25,860
<b>आयातों में बाजार हिस्सा</b>					
संबद्ध देश	%	77.29%	64.80%	54.75%	49.69%
अन्य	%	22.71%	35.20%	45.25%	50.31%
कुल आयात	%	100.00	100.00	100.00	100.00



भारतीय उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
मांग	मी.टन	68,275	75,459	90,088	1,05,145
- के संबंध में संबद्ध देशों से आयात					
भारतीय उत्पादन	%	45.35%	26.54%	20.74%	16.12%
खपत	%	28.41%	19.10%	15.16%	12.22%

53. यह नोट किया गया है कि में क्षति अवधि में संबद्ध देशों से आयात की मात्रा में कुल रूप गिरावट आई है। जारी पृथक पाटन रोधी जांच के तहत अन्य देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।

54. आयातों की मात्रा और आगे की जांच आयातों को मोनो और मल्टी फिलामेंट में अलग-अलग बांट कर और जांच की गई है। यह देखा गया है कि मोनो फिलामेंट यार्न की मात्रा कुल मिलाकर समान स्तर पर बनी रही है, जैसा कि नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है :-

विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिक)
संबद्ध देशों से पाटित आयात	मी.टन	19400	14415	13659	12849
मोनो फिलामेंट यार्न	मी.टन	7290	2596	1536	959
मल्टी फिलामेंट यार्न	मी.टन	12109	11819	12123	11890

### च. 3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव और घरेलू उद्योग पर उनका प्रभाव

55. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत में कथित पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा रूप से कीमतों में हास करता है या कीमतों में वृद्धि को रोकता है, जो अन्यथा रूप से सामान्य अवधि में घटित हुआ होता। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की कीमत में कटौती, कीमत से कम कीमत पर बिक्री, कीमत दमन और कीमत हास, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एन एस आर) और क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) की संबद्ध देशों से आयातों की पहुंच लागत के साथ तुलना की गई है। प्राधिकारी ने पी सी एन आधार पर कीमत कटौती और कीमत से कम कीमत पर बिक्री का विश्लेषण किया गया है क्योंकि अलग-अलग पी सी एन की प्रति कि.ग्रा. कीमतों में महत्वपूर्ण भिन्नता है।

#### क) कीमत में कटौती

56. कीमत कटौती के लिए व्यापार के समालन स्तर पर घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत तथा उत्पाद के पहुंच मूल्य के बीच निवल दरों और करों पर तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतों को कारखानागत स्तर पर निर्धारित किया गया था।

विवरण	यूनिट	चीन	इंडोनेशिया	कोरिया	मलेशिया	ताइवान	थाईलैंड
आयातों की पहुंच कीमत	रू./मी.टन	190,282	188,643	171,467	160,614	175,455	174,334
निवल बिक्री कीमत	रू./मी.टन	***	***	***	***	***	***

	न						
कीमत कटौती	रू./मी.टन	***	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	5-15%	10-20%	20-30%	25-35%	15-25%	15-25%

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पीओआई के दौरान, कथित पाटित आयातों का कीमत कटौती प्रभाव सभी संबद्ध देशों के संबंध में सकारात्मक है।

**ख) कीमत से कम कीमत पर बिक्री**

58. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा झेली जा रही कीमत से कम कीमत पर बिक्री की भी जांच की है। तुलना पी सी एन वार की गई है और सभी संगणनाओं का भारांशित औसत निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	चीन	इंडोनेशिया	कोरिया	मलेशिया	ताइवान	थाईलैंड
आयातों की पहुंच कीमत	रू./मी.ट.	190,282	188,643	171,467	160,614	175,455	174,334
गैर क्षति-कारक कीमत	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रू./मी.ट.	***	***	***	***	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	10-20%	10-20%	15-25%	25-35%	20-30%	15-25%

59. उक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण कीमत से कम कीमत पर बिक्री की जा रही है।

60. **पाटित आयातों का कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रभाव:** यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का ह्रास अथवा न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण स्तर तक कीमतों को दमित करता है अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकता है, जो अन्यथा रूप से महत्वपूर्ण स्तर तक घटित हुआ होता, प्राधिकारी ने क्षति अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तन पर विचार किया है। प्रास्थिति नीचे दी गई सारणी के अनुसार दर्शाई गई है:-

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई (वार्षिक)
बिक्री की लागत	रू./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	96	81
बिक्री कीमत	रू./मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	102	100	85
पहुंच कीमत	रू./मी.टन	241,250	235,746	216,937	171,062
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	90	71

61. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में बिक्री की लागत और बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई है। बिक्री कीमत में ह्रास केवल पी ओ आई के दौरान हुआ है, हालांकि, आरंभिक क्षति अवधि के दौरान नहीं हुआ। तथापि, बिक्री कीमत की अपेक्षा लागत में अधिक गिरावट आई है।

**च.3.3 घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक पैरामीटरों की जांच**

62. ए.डी. नियमावली के अनुबंध- II में अपेक्षा की गई है कि क्षति के निर्धारण में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव की उद्देश्यात्मक जांच शामिल होगी। ए.डी. नियमावली में आगे व्यवस्था की गई है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उन सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का उद्देश्य पूर्ण और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होगा जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें बिक्रियों में वास्तविक और संभावित गिरावट, लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर वापसी या क्षमता का उपयोग, घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकदी प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, इन्वेंटरीज, रोजगार, मजदूरी वृद्धि, पूंजीगत निवेशों को जुटाने की क्षमता शामिल है।

63. तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों का यहां नीचे विश्लेषण किया गया है: **क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्रियों पर वास्तविक और संभावित प्रभाव**

64. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री पर वास्तविक और संभावित प्रभावित निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	वार्षिकी पीओआई
क्षमता	मी.टन	***	***	***	***
उत्पादन	मी.टन	***	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	81.15%	84.61%	88.10%	87.06%
बिक्री	मी.टन	***	***	***	***
मांग/खपत	मी.टन	68,275	75,459	90,088	1,05,145

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने देश में विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में वृद्धि के अनुक्रम में क्षति की अवधि में अपनी क्षमता में वृद्धि की है। घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा में भी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है।

**ख. मांग में बाजार हिस्सा**

66. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से पर पाटित आयातों के प्रभावों की निम्नानुसार जांच की गई है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है परंतु अन्य भारतीय उत्पादकों के बाजार हिस्से में काफी वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	43.27%	49.49%	44.61%	42.19%
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	%	19.97%	21.03%	27.70%	33.21%
संबद्ध देशों से आयात	%	28.41%	19.10%	15.16%	12.22%
अन्य देशों से आयात	%	8.35%	10.38%	12.53%	12.37%
मांग/खपत	%	100.00	100.00%	100.00%	100.00%

**ग. माल सूची**

67. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के औसत मालसूची स्तर पूरी क्षति अवधि के दौरान लगभग समान बने रहे हैं।

विवरण	यूओएम	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
औसत स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***

**घ. निवेश और नकदी प्रवाह पर लाभ वापसी**

68. लाभ, निवेश पर वापसी और नकदी प्रवाह के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	रू./मी.टन	***	***	***	***
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	सूचीबद्ध	(100)	(52)	(5)	14
लाभ/(हानि) - जोड़	करोड़ रु.	***	***	***	***
लाभ/(हानि) - जोड़	सूचीबद्ध	(100)	(66)	(6)	21
<b>मोनो फिलामेंट यार्न</b>					
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	रू./मी.टन	***	***	***	***
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	सूचीबद्ध	100	14	17	132
लाभ/(हानि) - जोड़	करोड़ रु.	***	***	***	***
लाभ/(हानि) - जोड़	सूचीबद्ध	100	15	19	147
<b>मल्टी फिलामेंट यार्न</b>					
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	रू./मी.टन	***	***	***	***
लाभ/(हानि) प्रति यूनिट	सूचीबद्ध	(100)	(38)	(7)	(19)
लाभ/(हानि) - जोड़	करोड़ रु.	***	***	***	***
लाभ/(हानि) - जोड़	सूचीबद्ध	(100)	(50)	(10)	(30)
ब्याज और कर पूर्व लाभ	करोड़ रु.	***	***	***	***
ब्याज और कर पूर्व लाभ	सूचीबद्ध	(100)	350	750	950
मोनो फिलामेंट	करोड़ रु.	***	***	***	***
मोनो फिलामेंट	सूचीबद्ध	100	47	47	126
मल्टी फिलामेंट	करोड़ रु.	***	***	***	***
मल्टी फिलामेंट	सूचीबद्ध	(100)	23	100	59
नियोजित पूंजी पर वापसी - एन एफ ए	%	***	***	***	***
नियोजित पूंजी पर वापसी - एन एफ ए	सूचीबद्ध	(100)	349	770	840
मोनो फिलामेंट	%	***	***	***	***
मोनो फिलामेंट	सूचीबद्ध	100	47	53	132
मल्टी फिलामेंट	%	***	***	***	***
मल्टी फिलामेंट	सूचीबद्ध	(100)	19	79	43

69. यह देखा गया है कि मोनो फिलामेंट में घरेलू उद्योग लाभ अर्जित कर रहा है जिसमें आयात कम है और मल्टी फिलामेंट यार्न में हानि झेल रहा है जहां आयात सापेक्ष रूप से अधिक है। इसी प्रकार निवेश पर वापसी मोनो फिलामेंट यार्न

की तुलना में मल्टी फिलामेंट यार्न पर काफी कम है। तथापि, समग्र आधार पर, वापसी की दर तथा लाभप्रदता में सुधार हुआ है।

#### ड. उत्पादकता

70. नीचे दी गई सारणी से यह देखा जा सकता है कि दैनिक तथा प्रति कर्मचारी उत्पादकता की शर्तों में, उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है जो उत्पादन संचलन के क्रम में है:

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
उत्पादकता प्रतिदिन	मी.टन/दिन	***	***	***	***
उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी.टन/सं.	***	***	***	***

#### च. रोजगार और मजदूरी

71. नीचे दी गई सारणी से यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास रोजगार में गिरावट आई है। तथापि, अदा की गई मजदूरियों में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये मापदंड अन्य मापदंडों की बड़ी संख्या पर निर्भर है और घरेलू उद्योग पर पाटन के प्रभाव को प्रतिबिंबित नहीं करते।

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई
रोजगार	संख्या	***	***	***	***
मजदूरी	लाख रु. में	***	***	***	***

#### छ. वृद्धि

72. नीचे दी गई सारणी दर्शाती है कि घरेलू उद्योग ने मात्रा पैरामीटरों के रूप में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है जैसे बिक्री मात्रा, उत्पादन, क्षमता उपयोग। इसके अतिरिक्त मोनो फिलामेंट यार्न के लिए कीमत पैरामीटरों के रूप में और अधिक वृद्धि हुई है जिनमें आयात कम रहे हैं जबकि मल्टी फिलामेंट यार्न के मामले में यह नकारात्मक है जहां आयात कमोबेश स्थिर रहे हैं।

विवरण	यूनिट	2012-13	2013-14	2014-15	पीओआई(क)
उत्पादन	%	-	27%	8%	9%
घरेलू बिक्री	%	-	26%	8%	10%
क्षमता उपयोग	%	-	3%	3%	-1%
मोनो फिलामेंट यार्न					
लाभ	%	-	-85%	24%	680%
निवेश पर वापसी	%	-	-53%	14%	147%
मल्टी फिलामेंट यार्न	%	-			
लाभ	%	-	50%	80%	-202%
निवेश पर वापसी	%	-	119%	318%	-46%

#### ज. पूंजीगत निवेश को जुटाने की क्षमता

73. घरेलू उद्योग ने देश में उत्पादन की वर्तमान और संभावित मांग पर विचार करते हुए विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाया है।

**झ. पाटन और पाटन मार्जिन का स्तर**

74. यह नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से अभी आयात भी पाटित कीमतों पर देश में प्रवेश कर रहे हैं।

**ञ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

75. जांच इस ओर संकेत करती है कि संबद्ध वस्तुओं की भारत में लाभप्रद मांग है। यह भी देखा गया है कि संबंध देशों से संबद्ध वस्तुओं का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की गैर क्षतिकारक कीमत और बिक्री कीमत से कम है। याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि अन्य देशों अर्थात् यूरोपीय संघ (ई.यू.) और वियतनाम से भी आयात पाटित और क्षतिकारक कीमत पर बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।

**ट. क्षति और क्षति मार्जिन की मात्रा**

76. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं की गैर-क्षतिकारक कीमत, जैसी कि ए.डी. नियमावली के अनुबंध- III की शर्तों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है, की पी.ओ.आई. के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना की गई है और इस प्रकार तैयार किया गया क्षति मार्जिन निम्नानुसार है:-

विवरण	अमरीकी डॉलर/मी.टन
विनिमय दर	***
गैर क्षति कारक कीमत (एन आई पी)	***
पहुंच कीमत	2571.15
क्षति मार्जिन	***
क्षति मार्जिन -%	***
क्षति मार्जिन (रेंज)	20-30%

**ठ. अन्य ज्ञात कारक एवं कारणात्मक संबंध**

77. इसकी कीमत कटौती एवं कीमत ह्रास और न्यूनीकरण प्रभावों के रूप में घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के लगातार क्षति, मात्रा और कीमत प्रभावों की विद्यमानता की जांच करते हुए भारतीय नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य सांकेतिक पैरामीटरों और पाटनरोधी करार की प्राधिकारी द्वारा यह देखने के लिए निम्नानुसार जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अतिरिक्त, कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सकता है:

**क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें**

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यूरोपीय संघ और वियतनाम से देश में प्रवेश करने वाले आयात न्यूनतम स्तर से अधिक हैं और इसकी एक पृथक जारी पाटनरोधी जांच जारी है। वियतनाम और यूरोपीय संघ से आयात भी मल्टी फिलामेंट श्रेणी में आते हैं।

**ख. मांग का संकुचन**

79. क्षति अवधि में संबंधित उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है।

**ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

80. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए, खपत के पैटर्न में परिवर्तन को घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं समझा जा सकता।

**घ. प्रौद्योगिकी में परिवर्धन**

81. संबंधित उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं। इसलिए प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों को घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

**ड. प्रतिस्पर्धा और व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियों की शर्तें**

82. ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति नहीं है जो घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान कर सकती है।

**च. घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन**

83. घरेलू उद्योग के निष्पादन और उसे होने वाली क्षति की यथासंभव सीमा तक घरेलू निष्पादन के संबंध में जांच की गई है। इसलिए, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन में संभावित ह्रास घरेलू उद्योग को क्षति का संभव कारण नहीं है।

**छ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्री किए गए उत्पादों का निष्पादन**

84. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों के निष्पादन ने घरेलू उद्योग के निष्पादन की प्राधिकारी द्वारा किए गए आकलन को प्रभावित नहीं किया है। प्राधिकारी द्वारा विचारित की गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है।

**ज. घरेलू उद्योग की उत्पादकता**

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता ने उत्पादन के रूप में समान प्रवृत्ति का अनुसरण किया है और वृद्धि दर्शाई है। उत्पादकता में ह्रास घरेलू उद्योग के क्षति का कारण नहीं है।

**कारणात्मक संबंध से संबंधित कारक**

86. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- विचाराधीन उत्पादन का पाटन हुआ है।
- सभी संबद्ध देशों के संबंध में पाटित आयातों का कीमत कटौती प्रभाव सकारात्मक है।
- लाभप्रदता के अतिरिक्त, सभी संगत आर्थिक पैरामीटरों पर घरेलू उद्योग की स्थिति में कुल मिलाकर सुधार हुआ है।
- समग्र लाभप्रदता ने भी लगातार सुधार दर्शाया है। तथापि, यह मुख्य रूप से मोनो फिलामेंट यार्न खंड में बेहतर निष्पादन के कारण है जहां संबद्ध देशों से आयात सापेक्ष रूप से काफी कम है।

**हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात विवरण संबंधी अनुरोध**

87. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों से प्रकटन पश्चात अनुरोध प्राप्त हो गए हैं। उनमें उठाए गए अधिकतर मुद्दे जांच की अवधि के दौरान पहले ही उठा दिए गए हैं और उनका समुचित रूप से समाधान भी कर दिया गया है। अतिरिक्त अनुरोधों का निम्नलिखित रूप में विश्लेषण किया गया है।

**घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

88. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध का सार निम्नलिखित है :-

- i. पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना का विश्लेषण निर्णायक समीक्षा जांच में सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है। तथापि, प्रकटन विवरण जांच के इस महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में अनिवार्य तथ्यों के बारे में पूर्णतः मौन है। प्रकटन विवरण उस सीमा तक निरर्थक हो गया है जब घरेलू उद्योग संभावना के निर्धारण के लिए माने जा रहे तथ्यों की उपयुक्तता के संबंध में टिप्पणी करने में समर्थ न हो।
- ii. प्रकटन विवरण से उभरने वाले निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :-
  - क. याचिकाकर्ता एवं घरेलू उत्पादक भारत में संबद्ध सामानों के पात्र घरेलू उत्पादक हैं और उनका उत्पादन भारतीय उत्पादन के प्रमुख अनुपात में बना हुआ है।
  - ख. विचाराधीन उत्पाद सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप संबद्ध देशों से पाटन जारी है।
  - ग. आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाए जा रहे हैं जैसा कि इस अवधि में उसके निष्पादन से सिद्ध है।
  - घ. घरेलू उद्योग का निष्पादन एकल फिलामेंट में वहां सुधरा है जहां आयात बहुत तेजी से कम हुए हैं और मात्रा में भी कम है तथा बहु-फिलामेंट यार्न में निष्पादन कम हुआ है जहां आयात महत्वपूर्ण हैं तथा पाटन जारी है।

ड. पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटन का समाधान करने के लिए जारी रखा जाना अपेक्षित है।

iii. विचाराधीन उत्पाद नायलोन का सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है जिसे पालीमाइंड यार्न के रूप में भी जाना जाता है (नायलोन फिलामेंट यार्न के रूप में भी वर्णित है तथा उसे संबद्ध सामान के रूप में उल्लिखित किया गया है)। नायलोन फिलामेंट यार्न ऑर्गेनिक मोनोमर्स के पालीमराइजेशन द्वारा उत्पादित सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते और पाटनरोधी शुल्क प्राधिकारी द्वारा पूर्व में सिफारिश की गई संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर लागू होने के नाते, यह सही माना गया है कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जैसाकि मूल एवं बाद की समीक्षा जांच में है और इसीलिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से एकल फिलामेंट यार्न को हटाने के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिया गया तर्क सही-सही उपेक्षित किया गया है। बहु फिलामेंट यार्न के मामले में क्षति जारी है। एकल फिलामेंट यार्न घरेलू प्रचालनों तथा निर्यातक के प्रचालन का एक महत्वपूर्ण भाग बना हुआ है।

iv. मै. जेसीटी लिमिटेड, मै. गुजरात पालीमर्स प्रा. लि., मै. गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि., मै. प्रफुल्ल ओवरसीज प्रा.लि. और एवाईएम सिंटेक्स (जिसे पहले वेल्सपन सिंटेक्स के रूप में जाना जाता था) द्वारा आवेदन दायर किया गया था और उसका समर्थन सलासर, जेपीबी फाइबर, गुप्ता सिंथेटिक्स लि., सेंचुरी एंका और ओरिलन इंडिया प्रा. लि. ने किया था। मै. जेसीटी लिमिटेड और मै. एवाईएम सिंटेक्स को छोड़कर किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा आयात नहीं किए गए हैं और वह भी बहुत कम हैं तथा इससे उपर्युक्त कंपनियां घरेलू उद्योग माने जाने के लिए अपात्र नहीं हो जाती।

v. याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादन भारतीय उत्पादन का बड़ा भाग बना हुआ है। याचिकाकर्ता नियमों के अभिप्राय के अंतर्गत पात्र घरेलू उद्योग हैं।

vi. जांच की अवधि अप्रैल, 2015 से सितंबर, 2016, (18 माह) के बीच पड़ती है और यह अवधि चायनीज एसेसन प्रोटोकॉल के ठीक पहले की है। अतः हितबद्ध पक्षकारों को सामान्य मूल्य के परिकलन की पद्धति पर और चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माने जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चीन के किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है।

vii. घरेलू उद्योग की वास्तविक उत्पादन लागत को सामान्य मूल्य माना जाए। जोकि सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर है। कृपया सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन संशोधित करें।

viii. मांग पूरी क्षति अवधि में बढ़ी है। संबद्ध देशों से आयात काफी रहे हैं जबकि अन्य देशों से पाटित आयात बढ़े हैं।

ix. कीमत कटौती और क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं।

x. पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत तथा एनआईपी से काफी कम है और इस प्रकार घरेलू उद्योग की कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री हो रही है।

xi. कीमत न्यूनीकरण पाटित आयातों के कारण है।

xii. लागत में कमी के संबंध में विश्लेषण बिक्री कीमत से अधिक है, जो अपूर्ण है। बिक्री कीमत जांच की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में लागत में कमी से अधिक कम हुई है। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग पाटन के विगत कुप्रभावों से उभरने की प्रक्रिया में है, वर्तमान मामले में क्षति दर्शाने वाला एक क्षति संबंधी मानदंड है।

xiii. बिक्री कीमत उत्पादन लागत के स्तर से कम बनी हुई है। आयात का पहुंच मूल्य बिक्री कीमत और उत्पादन लागत के स्तर से काफी कम है। शुल्क बंद करने से पहले से ही हो रही हानियों को और अधिक करने की संभावना बताता है।

xiv. घरेलू उद्योग का उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग क्षति अवधि में बढ़ा है।

xv. मालसूची उसी रेंज में रही है और वह काफी है।

xvi. घरेलू उद्योग पाटन के कारण पूरी क्षति अवधि में हानियां उठा रहा है। उसे हुई वित्तीय हानियां पूरी क्षति अवधि में घटती प्रवृत्ति दर्शाती हैं तथापि, वे काफी रही हैं। घरेलू उद्योग को बहु फिलामेंट यार्न में वित्तीय हानियां हुई हैं जबकि एकल फिलामेंट यार्न में उसने लाभ अर्जित किए हैं जहां आयात काफी कम हुए हैं जो यह दर्शाता है कि बहु फिलामेंट यार्न में प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट रूप से पाटित आयातों के कारण है।

xvii. प्रति कर्मचारी एवं प्रतिदिन उत्पादकता क्षति अवधि में बढ़ी है जो उत्पादन के अभियान के अनुरूप है।



- xxviii. वृद्धि संबंधी मानदंड ये दर्शाते हैं कि एकल फिलामेंट यार्न में वृद्धि में सुधार हुआ है जबकि बहु फिलामेंट यार्न में कमी आई है।
- xxix. प्राधिकारी द्वारा निकाला गया पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक एवं काफी है। संगत अवधि के दौरान भारत से जिस मात्रा में भी निर्यात किया गया है, वह पाटित कीमतों और क्षतिकारक कीमत पर है।
- xx. एक निर्णायक समीक्षा जांच होने के नाते प्राधिकारी साथ-साथ पाटन के जारी रहने/बार-बार होने तथा उसकी संभावना के संबंध में समाधान करने में विफल रहे हैं और इसीलिए याचिकाकर्ता पाटन एवं क्षति की संभावना के संबंध में अनुरोधों को दोहराते हैं।
- xxi. आयातों से जांच की अवधि में सकारात्मक पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन हो रहा है जो शुल्क बंद करने की स्थिति में पाटन एवं क्षति की संभावना दर्शाते हैं। विगत कई मामलों में, जिनमें जांच की अवधि के दौरान सकारात्मक क्षति मार्जिन पाया गया है, प्राधिकारी ने माना कि शुल्क बंद करने से पाटन एवं क्षति की संभावना होगी।
- xxii. एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी या तो विभिन्न कानूनी प्रावधान के आधार पर जब तक सिद्ध न हो जाए अथवा मामले के उन तथ्यों जिनमें विगत निर्धारण बाध्यकारी नहीं है और जिन्हें उपेक्षित किए जाने की आवश्यकता है, के पूर्व निर्धारणों से बाध्य हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी को एटीएमए बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अर्ध न्यायिक प्राधिकारी माना गया है।
- xxiii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने माना है कि पाटनरोधी शुल्क आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है जब कीमत कटौती, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन सकारात्मक हों; जब घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो, चाहे वर्तमान अथवा अन्य स्रोतों से हो; जब घरेलू उद्योग को जारी क्षति पाटित आयातों के सिवाय अन्य कारकों से न हो। यही स्थिति पूर्णतः वर्तमान मामले में बनी हुई है।
- xxiv. घरेलू उद्योग को वियतनाम एवं यूरोपीय संघ से पाटित आयातों से क्षति हो रही है परंतु इस तथ्य का कि उसे किन्हीं अन्य स्रोतों से पाटित आयातों से क्षति हो रही है, अभिप्राय यह नहीं है कि उसे वर्तमान स्रोतों से पाटन अथवा क्षति की संभावना नहीं है।
- xxv. पाटन पहले ही प्रकटन विवरण में सिद्ध है। ऐसे मामले में यह पूर्णतः अवास्तविक है कि क्या पाटन एक पाटित स्रोत अथवा अन्य पाटित स्रोत से है। घरेलू उद्योग को क्षति पर विचार करते समय पाटित आयात का स्रोत संगत नहीं है। वियतनाम एवं यूरोपीय संघ में जारी जांच की शुरुआत का नोटिस स्पष्ट रूप से प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति को सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण है।
- xxvi. एसएसआर मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को अलग-अलग निर्यात लेन-देनों में निर्यातकों के व्यवहार की जांच किए बिना संभावना के संबंध में निर्णय नहीं ले सकते। इस मामले में सूचना मांगे जाने के बाद भी उसे प्रकटन विवरण में स्वीकार नहीं किया गया है। प्राधिकारी कृपया उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर भाग-2 पर ओर विशेष रूप से वैश्विक रूप से विभिन्न देशों को उत्तरदाता निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातकों के बीजक विवरणों द्वारा बीजक पर विचार करें। प्राधिकारी कृपया तीसरे देशों को अलग-अलग निर्यात लेनदेनों में पाटन एवं क्षति मार्जिन का निर्धारण करें तथा ऐसे पाटित आयातों पर अलग से विचार किया जाना चाहिए फिर तीसरे देशों के निर्यातों में अलग-अलग क्षति मार्जिन निर्धारित करने के लिए संचित किया जाना चाहिए।
- xxvii. संबद्ध देशों पर पाटनरोधी शुल्क आंशिक रूप से लगाए जाने से दूसरे देशों से पाटन होने लगा। संबद्ध सामानों का उत्पाद करने वाले ताइवान में एक संयंत्र का प्रचालन करने वालो फार्मोसा गुप की एक समूह कंपनी फार्मोसा इंडस्ट्रीज कार्प ने वियतनाम में अपनी कंपनी के माध्यम से पाटन किया है। उसने वियतनाम और यूरोपीय संघ के संबंध में संबद्ध सामानों के विरुद्ध नई जांच में उत्तर दिया है। वह ताइवान से पाटन कर रही थी और अब उसने वियतनाम में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित कर दी हैं तथा इसीलिए यह एक स्रोत से दूसरे स्रोत में पाटन मा स्पष्ट मामला है।
- xxviii. संबद्ध सामानों का विनिर्माण करने वाली कोरिया में एक कंपनी हियोसुग कार्पोरेशन ने वियतनाम में अपनी संबद्ध कंपनी के माध्यम से पाटन किया है।
- xxix. प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में खुद ही नोट किया है कि “वियतनाम से काफी मात्रा में घरेलू बाजार में आयात आने शुरू हो गए हैं, इस प्रकार पाटन में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है”। यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि यदि वर्तमान शुल्क हटा दिए जाएं और वे नए देशों पर लगाए जाएं तो वर्तमान जांच में संबद्ध देश पुनः पाटन की परिपाटी का सहारा लेंगे।

xxx. संबद्ध देशों से उत्पादकों के पास संबद्ध देशों में संबद्ध सामानों की मांग की तुलना में पर्याप्त अधिशेष क्षमताएं हैं। इसे प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से की गई निर्णायक समीक्षा जांच में माना गया था।

xxxi. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया उपलब्ध क्षमता, निर्यातानुमुखता तथा तीसरे देशों के निर्यात के संबंध में निर्यातकों द्वारा दायर उत्तरों की जांच करें। इस बात की संभावना है कि निर्यातकों द्वारा दायर उत्तर पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में अधिक आयातों की संभावना दर्शाएंगे।

xxxii. पूर्व जांचों से काफी आयात की मौजूदगी सिद्ध हुई है। वर्तमान जांच अवधि के लिए निर्धारित पाटन मार्जिन भी काफी अधिक है जो स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि पाटन वर्तमान शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में जारी रहने और बढ़ने की संभावना है।

xxxiii. चीन द्वारा भारत को निर्यात किए जा रहे संबद्ध सामानों की कीमत पाटन एवं क्षति के जारी रहने की संभावना का एक संकेतक है। आयात घरेलू उद्योग की कीमत को काफी कम कर रहे हैं। आयात पाटित एवं क्षतिकारक कीमत पर किए जा रहे हैं। शुल्क बंद करने से विदेशी उत्पादकों के लिए भारतीय कीमतें काफी आकर्षक होने की संभावना है।

xxxiv. घरेलू उद्योग को काफी समय से पाटित आयातों से क्षति हुई जैसा कि पूर्व जांचों के निर्धारण से पुष्टि हुई है जो स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करता है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों से क्षति के लिए सुभेद्य है। इस बात की संभावना है कि शुल्क समाप्त होने से भारतीय बाजार में सामग्री की बाढ़ आ जाएगी।

xxxv. केवल एक निर्यातक ने प्राधिकारी को उत्तर दिया है और संभावना न होने का दावा किया है। मलेशियायी निर्यातक ने अनुरोध दायर नहीं किए हैं तथा संभावना न होने का दावा भी नहीं किया है। कंपनी को विचाराधीन उत्पाद के संबंध में अपने व्यापार में काफी वित्तीय हानियां हो रही हैं और उसकी कम घरेलू बिक्री है तथा तीसरे देशों को काफी निर्यात हैं जो हानिकारक माने जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि शुल्क बंद करने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।

xxxvi. इंडोनेशियाई निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि उसका पूर्णतः उपयोग हो रहा है तथा घरेलू उद्योग को बढ़ी हुई क्षति होने की संभावना नहीं है। उसने कई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए हैं और झूठे तथा भ्रामक विवरण दिए हैं। वह बढ़ती हुई मालसूची पर बैठा है और तीसरे देशों को भारी मात्रा में निर्यात कर रहा है जोकि भारत से भी कम कीमतों पर है जबकि इसे भारी वित्तीय हानियां होना समझा जाता है। इस प्रकार घरेलू उद्योग तथा निर्यातकों को वित्तीय हानियां हो रही हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निर्यातक पाटन का सहारा ले रहे हैं और बाजार अवसरों की ओर देख रहे हैं।

xxxvii. एसएसआर जांच के लिए हाल ही में जारी किए गए व्यापार नोटिस में उल्लिखित शर्तें वर्तमान मामले में पूर्णतः पूरी की गई हैं जैसाकि निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तर तथा याचिका से देखा जाएगा। यहां तक कि प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित मानदंडों को देखते हुए मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना दर्शाते हैं।

xxxviii. यह आवश्यक नहीं कि शुल्क जारी रखने के लिए सभी शर्तें मौजूद हों। ऐसे कई मामले हैं जब एक या अधिक मानदंड पूरे होने पर भी शुल्क जारी रखा गया है।

xxxix. पाटनरोधी शुल्क का रूप सभी तरह के संबद्ध सामानों के लिए पाटनरोधी शुल्क (शुल्क का निर्धारित स्वरूप) की निर्धारित मात्रा होना चाहिए।

xl. शुल्क अमरीकी डॉलर के संदर्भ में लगाए जाएं। रूपए का काफी मूल्यह्रास हुआ है अतः निश्चयात्मक शुल्क कृपया अमरीकी डॉलर में व्यक्त किया जाए।

### **अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

89. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का सार निम्नलिखित है :-

#### **पीटी इंडाची, प्राइमा, इंडोनेशिया की ओर से प्रकटन पश्चात अनुरोध**

i. संबद्ध सामान 10 वर्षों से पाटनरोधी शुल्क के अध्वधीन है। वर्तमान मामले के अनिवार्य तथ्य किन्हीं विशेष परिस्थितियों को प्रकट नहीं करते जो पाटनरोधी शुल्क जारी करने के लिए आवश्यक हों। यह सिद्धांत ड्राइ सैल बैटरीज के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के दिनांक 20 मई, 2013 के अंतिम जांच परिणाम से उभरता है जिसमें प्राधिकारी ने माना है कि 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए शुल्क जारी न रखना प्राधिकारी का कार्य होगा।

ii. इंडोनेशिया से आयात कुल आयातों में केवल 2.68 प्रतिशत है और उसका बाजार हिस्सा 0.66 प्रतिशत है। इतने कम आयात से क्षति के लिए कोई मात्रात्मक अथवा कीमत प्रभाव नहीं हो सकता। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के पैरा

3 के साथ पठित नियम-11 यह अधिदेश करता है कि जहां आयात 3 प्रतिशत से कम हैं वहां उन्हें क्षति के मूल्यांकन के लिए अन्य संबद्ध देशों के आयात के साथ संचित नहीं किया जा सकता। इंडोनेशिया से आयात अन्य संबद्ध देशों के आयातों के साथ संचित नहीं किए जाने चाहिए।

iii. विगत में इसी प्रकार के मामलों में जहां आयात नगण्य थे, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने निर्णायक समीक्षा रद्द कर दी। ऐसे मामले चीन जन.गण. और इंडोनेशिया के फ्लोट ग्लास (अंतिम जांच परिणाम दिनांक 2 जुलाई, 2015) के हैं जिनमें समीक्षा इंडोनेशिया के विरुद्ध तथा चीन जन गण से शुल्क ड्राइ सैल बेटरीज के विरुद्ध रद्द की गई थी (अंतिम जांच परिणाम दिनांक 20 मई, 2013) जिनमें चीन जन.गण. के विरुद्ध तथा चीन जन.गण. और स्वीडन से पेंटारीथ्रिटोल (अंतिम जांच परिणाम दिनांक 25 मार्च, 2011) के विरुद्ध समीक्षा रद्द की गई थी, जिनमें स्वीडन के विरुद्ध समीक्षा रद्द की गई थी।

iv. एकल फिलामेंट यार्न के आयात से कोई मात्रात्मक प्रभाव/कीमत प्रभाव नहीं है। कोई कीमत न्यूनीकरण भी नहीं है। घरेलू उद्योग इस क्षेत्र में काफी लाभ में है और इस क्षेत्र में निवेश पर आय भी बहुत अधिक है।

v. क्षति की अवधि में उत्पादन, घरेलू बिक्री, निवेश पर आय और लाभप्रदता में वृद्धि में भी काफी सुधार आया है।

vi. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक है और भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा जांच की अवधि के दौरान (क) 75 प्रतिशत से अधिक है। घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जांच की अवधि (क) के दौरान 87 प्रतिशत है। बिक्री कीमत में कमी बिक्री की लागत में कमी से कम है जो यह दर्शाता है कि कोई कीमत न्यूनीकरण नहीं है।

vii. इंडोनेशिया में अधिशेष क्षमता नहीं है, इंडोनेशिया से संबद्ध सामानों के निर्यात पर पाटनरोधी शुल्क नहीं है और भारत में एकल फिलामेंट यार्न की मांग का सिकुड़ना यह दर्शाता है कि इंडोनेशिया से पाटन एवं क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना नहीं है।

viii. घरेलू उद्योग की क्षति संबंधी सूचना प्रकटन विवरण में नहीं बताई गई है, यथा- क्षमता, उत्पादन, बिक्री, उत्पादकता, औसत स्टॉक, रोजगार तथा मजदूरी। यहां तक कि उसकी सूचीबद्ध संख्या भी नहीं दी गई है। ये आंकड़े प्रकट किए जाने चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने इसके संबंध में किसी गोपनीयता का दावा नहीं किया है।

ix. अनुरोध है कि एकल फिलामेंट यार्न पर पाटनरोधी शुल्क तथा इंडोनेशिया के विरुद्ध शुल्क बंद किया जाए।

x. यदि प्राधिकारी शुल्क जारी रखने का निर्णय लेते हैं तो नायलोन 6 एकल फिलामेंट यार्न पर शुल्क वहीं होना चाहिए जो मूल जांच तथा बाद की निर्णायक समीक्षा में किया गया है।

### छ. प्राधिकारी द्वारा जांच

90. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकतर अनुरोध पुनरावृत्ति के रूप में हैं और प्रकटन विवरण में पूर्व में ही उनका समाधान पहले ही कर दिया गया है। उपर्युक्त जांच परिणाम पक्षकारों के इन तर्कों के संबंध में है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच संगत होने की सीमा तक निम्नलिखित रूप में की है और अन्यत्र उन पर विचार नहीं किया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि पाटन एवं क्षति की संभावना की जांच की जानी चाहिए थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके विपरीत पाटित आयातों की मात्रा निरंतर कम हुई है। इसी प्रकार, आयात निश्चित रूप से घरेलू कीमतों पर काफी न्यूनीकरण अथवा ह्रास का प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटन एवं क्षति की संभावना के लिए अन्य मानदंडों, यथा- संबद्ध देश के निर्यातकों के पास पर्याप्त स्वतंत्र निपटान योग्य क्षमता की उपलब्धता अथवा किसी भी अतिरिक्त निर्यात को लेने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में पाटित निर्यातों की काफी वृद्धि की संभावना की जांच एक ऐसा कार्य है जो भविष्यवाणी करने के अभ्यास के समान है तथा प्राधिकारी इस प्रकार के कार्य में शामिल नहीं होना चाहते हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति के मूल्यांकन के लिए संगत सभी आर्थिक मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में स्पष्ट एवं दर्शनीय सुधार हुआ है।

क. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उत्पादन लागत के स्तर से कम है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा घोषित बिक्री कीमत जांच की अवधि से पूर्व के वर्षों के दौरान लागत से कम थी। तथापि, जांच की अवधि के दौरान इस स्थिति में परिवर्तन आया है। जांच की अवधि के दौरान बिक्री कीमत उत्पादन लागत से काफी अधिक थी।

ख. पीटी इंडाची प्राइमा द्वारा किए गए इस अनुरोध के संबंध में कि इंडोनेशिया से आयात विचाराधीन उत्पाद के आयात के 3 प्रतिशत से कम है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 14, नियम 23 के तहत की गई निर्णायक समीक्षा पर लागू नहीं होता।

#### ज. सिफारिशें

91. किए गए अनुरोधों और उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद तथा रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यद्यपि, विचाराधीन उत्पाद संबद्ध देशों से भारत को सामान्य मूल्य से कम पर निर्यात किया गया है, तथापि यह देखा जा सकता है कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति में सुधार हुआ है और पिछले 11 वर्षों के दौरान (लगभग) लागू पाटनरोधी शुल्क से उसका इच्छित प्रयोजन सिद्ध हुआ है।

92. अतः प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश नहीं करते हैं।

93. इस अंतिम जांच परिणाम की अधिसूचना के कारण केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

सुनील कुमार, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI- DUMPING AND ALLIED DUTIES)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2018

#### FINAL FINDINGS

**Subject : Sunset Review of Anti-dumping duty imposed on the imports of Nylon Filament Yarn originating in or exported from China PR, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Korea RP.**

**F. No. 15/17/2016/DGAD.**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) thereof; the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) had initiated an anti-dumping investigation against import of Synthetic Filament yarn of Nylon also known as Polyamide Yarns and described as Nylon Filament Yarn originating in or exported from China PR, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Korea RP vide Notification No.14/5/2005-DGAD on 4<sup>th</sup> July, 2005 and preliminary findings were issued by the Authority on 3<sup>rd</sup> February, 2006. Provisional duties were imposed on 29<sup>th</sup> March, 2006 vide notification no. 30/2006-Customs. The Authority notified final findings on 3<sup>rd</sup> July, 2006 recommending imposition of definitive duties on imports of Nylon Filament Yarn originating in or exported from China PR, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Korea RP. The definitive anti-dumping duties on the subject goods imported from the subject countries were imposed by the Department of Revenue vide Customs Notification No. 85/2006 dated 29<sup>th</sup> August, 2006.

2. Whereas, the Authority undertook sunset review investigation and recommended continued imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries vide Notification No. 15/4/2010 - DGAD dated 19<sup>th</sup> November, 2011. Accordingly definitive anti-dumping duties were extended by the Central Government vide Notification No. 3/2012-Customs dated 13<sup>th</sup> January, 2012.

3. Whereas, M/s JCT Ltd, M/s Gujarat State Fertilizer Chemicals Ltd (GSFC), M/s Gujarat Polyfilms Pvt. Ltd. (GPPL), M/s Praful Overseas Pvt. Ltd, and M/s AYM Syntex Limited (hereinafter also referred to as “Petitioners” or “Applicants”) filed an application in the present case before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Act and the Rules for initiating sunset review of the anti-dumping duty on imports of Nylon Filament Yarn (hereinafter also referred to as the subject

goods), originating in or exported from China PR, Taiwan, Malaysia, Indonesia, Thailand and Korea PR (hereinafter also referred to as the subject countries) and requested for extension of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

4. Whereas, the Authority on the basis of prima facie evidence submitted by the applicants to justify initiation of sunset review investigation issued a public notice vide Notification No. 15/17/2016-DGAD dated 9<sup>th</sup> January, 2017 to examine whether the expiry of the said duties on the import of the subject goods originating in or exported from the subject countries are likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The validity of the antidumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries were extended by the Central Government up to 12<sup>th</sup> January, 2018, vide Notification No. 4/2017-Customs (ADD), dated 19<sup>th</sup> January, 2017.

5. The scope of the present review covers all aspects of the original investigation concerning imports of the above goods, originating in or exported from the subject countries.

#### **A. PROCEDURE**

6. Procedure described below has been followed with regard to this investigation, after issuance of the public notice notifying the initiation of the above investigation by the Authority:

- i. The Authority notified the Embassies/Representatives of the subject countries in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigations in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
- ii. The Authority sent a copy of the initiation notification to the embassy of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicants and requested them to make their views known in writing within 40 days of the initiation notification.
- iii. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
- iv. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from the subject countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
- v. The Authority sent Exporter's Questionnaire and Supplementary Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules :
  - a. M/s PT Susilia Indah Synthetic Fibre Industries, Indonesia
  - b. M/s PT Indachi Prima, Indonesia
  - c. M/s Recron (Malaysia) Sdn Bhd, Malaysia
  - d. M/s Hyosung Corporation, Korea
  - e. M/s Woongjin Chemicals Co. Ltd.
  - f. M/s Suntex Fibres , Taiwan
  - g. M/s Thai Taffeta Company Ltd. , Thailand
- vi. In response to the above notification, the following exporters/ producers responded and submitted questionnaire responses.
  - a. M/s PT Indachi Prima
  - b. M/s Recron (Malaysia) Sdn Bhd.
  - c. M/s PT Sulindafin
- vii. The Authority sent Importer's Questionnaires to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

- 
- a. Brakes India Private Limited
  - b. Baliga Fishnets
  - c. Birla Cable limited
  - d. D C Mills Pvt. Ltd.
  - e. Entremode Polycoaters Ltd.
  - f. Goenka Industries Private Limited
  - g. IDL Industries Ltd
  - h. Vivilon Textile Industries P
  - i. Garden Silks Mills Ltd.
  - j. SK Exports
  - k. Shalon Silk Industries Pvt. Ltd.
  - l. Suertex Industries. Ltd.
  - m. Valson Polyester Ltd.
  - n. Supreme India Impex Ltd.
  - o. Surat Synthetics Ltd.
  - p. Sarla Performance Fibers Ltd.
  - q. Kayavlon Impex Pvt. Ltd.
  - r. Euro Vista India Ltd.
  - s. SRF Ltd.
  - t. Habasit Iakoka Pvt. Ltd.
  - u. Garware Wall Ropes Ltd.
  - v. Dupont Fibers Ltd.
  - w. Chidambaram Fishnets Pvt. Ltd.
  - x. Bayer India Ltd.
  - y. AASU Textiles Private Ltd.
- viii. The following importers of the subject goods responded by filing questionnaire responses.
- a. M/s Pergo India Private Limited
  - b. M/s Daya Knitters
  - c. M/s Ginza Industries Limited
  - d. M/s Milan Textile
- ix. Further, one of the importers of the subject goods, M/s. Sarla Performance Ltd performance has submitted a letter opposing the imposition of anti-dumping duty.
- x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;
- xi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.

- xii. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Anti-dumping Rules has been worked out so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- xiii. Considering the fact that the subject goods are being imported in various grades/sizes/dimensions, the applicants have proposed Product Control Numbers (PCNs) in order to make a PCN to PCN comparison for computing the dumping margin and injury margin. Accordingly, the authority has made PCN to PCN comparison for the purpose of computing dumping and injury margins.
- xiv. The Authority held an oral hearing on 14<sup>th</sup> November, 2017 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally in accordance to Rule 6 (6), which was attended by the representatives of domestic industry and other interested parties. All the parties who presented their views in the oral hearing were requested to file written submissions of their views expressed orally. The parties were also advised to collect written submissions made by the opposing parties and were requested to submit their rejoinders thereafter.
- xv. The verification of the information provided by the domestic industry was carried out to the extent considered necessary. Only such verified information with necessary rectification, wherever applicable, has been relied upon.
- xvi. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review investigation is April, 2015 to September, 2016 (18 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014-March 2015 and the POI.
- xvii. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in this disclosure statement.
- xviii. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.
- xix. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- xx. ‘\*\*\*’ in this document represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- xxi. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as Rs.66.53 = 1 US\$.

## **B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE**

### **B.1 View of the Domestic industry**

- 7. The views of the domestic industry are as follows:
  - i. The present review investigation is a second sunset investigation. The product involved in the original and previous investigations and in the present sunset review investigation is Synthetic Filament yarn of Nylon also known as Polyamide Yarns and described as Nylon Filament Yarn. The product under consideration in the present sunset review is the same as has been held by the Designated Authority in the original investigation. Nylon Filament yarn is a synthetic filament yarn produced by polymerization of organic monomers.
  - ii. The subject goods are classified under heading Chapter 54 under customs subheading no. 5402 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation.

- iii. There is no difference in the technology employed and the quality of the domestic and imported product. Present investigation is a review investigation. The Designated Authority has examined the issue of product under consideration and like article in the original investigation, which is relied upon.

## **B.2 Views of the other interested parties**

- 8. Other interested parties have made the following submission -
  - i. There is no injury being faced by the domestic industry with respect to Mono filament yarn and imports are also low thus mono filament yarn should be excluded from the scope of product under consideration.
  - ii. The petitioners do not produce all grades of the subject goods and some applicants/supporters such as JCT, Century Enka and Salasar are also importing certain similar types of nylon yarns.
  - iii. Imports of certain yarns by some of the Petitioners/Supporters highlights non availability of such yarns in India. Such products must necessarily be excluded from the scope of the product under consideration
  - iv. Domestic industry is not in a position to supply Nylon 6 and 66 POY – 35D to 126D in 10F to 72F

## **B.3 Examination by the Authority**

9. The product under consideration in the present investigation is Synthetic Filament Yarn of Nylon, also known as Polyamide Yarns (also described as Nylon Filament Yarn and also referred to as subject goods). Nylon Filament Yarn is a synthetic filament yarn produced by polymerization of organic monomers.

10. The product under consideration includes all kinds of synthetic filament yarns of Nylon or Polyamides, other than sewing thread, such as flat yarn- twisted and/or untwisted, fully drawn yarn (FDY), spin drawn yarn (SDY), fully oriented yarn (FOY), high oriented yarn (HOY), partially oriented yarn (POY), textured yarn - twisted and/or untwisted, and dyed yarn, single, double, multiple, folded or cabled, classifiable within Chapter 54 under customs subheading no. 5402, but excludes high tenacity yarn of nylon or other polyamides.

11. The subject goods are classified under head the Chapter 54 under customs subheading no. 5402 of the Customs Tariff Act, 1975. However, the customs classification is indicative only and in no way binding on the scope of the subject investigation.

12. The present investigation being a sunset review investigation and anti-dumping duties, as earlier recommended by the Authority, being in force on the imports of the subject goods from the subject countries, the Authority considers that the scope of the PUC in the present investigation remains the same as that in the original and subsequent review investigation. .

13. As regards the claim that there are certain type of yarns that are not being produced by the domestic industry, the Authority notes that no supporting evidence has been furnished by other interested parties in this regard and hence the argument is not being accepted.

14. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

*"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*

15. After considering the information on record, the Authority holds that there is no known difference in product under consideration exported from subject countries and the subject product produced by the Indian industry. The subject goods produced by the domestic industry is comparable to the subject goods exported from subject countries in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably.

16. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the applicant domestic industry is like article to the product under consideration exported from the subject countries, in accordance with the AD Rules.



**C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING****C.1 Views of the domestic industry**

17. Following submissions have been made by the domestic industry:

- i. The petition has been filed by M/s JCT Ltd, M/s Gujarat Fertilizer Chemicals Ltd (GSFC), M/s Gujarat Polyfilms Pvt. Ltd. (GPPL), M/s Praful Overseas Pvt. Ltd, and M/s AYM Syntex Limited as domestic producers of the product under consideration and supported by Salasar Polytex, JPB Fiber (Eagle Group), Gupta Synthetics Limited, Orilon India Pvt Limited and Century Enka Limited
- ii. Production of petitioners constitutes a major proportion in Indian Production and therefore, the petitioners should be treated as “domestic industry” within the meaning of the Rules.
- iii. There is no legal requirement that each and every constituent of the domestic industry should be producing each and every type of the product under consideration. Considering the PCN parameters, there are potentially a very large number of product types. There can be no requirement for every producer to focus on every type of the product

**C.2 Views of the other interested parties**

18. The following submissions have been made in this regard –

- i. Petitioners consist of some producers who are importers of some grades/ types of nylon filament yarn and their inclusion in the scope of “domestic industry” merits reconsideration. Petitioner had included only four other companies- Salasar Polytex, JPB Fiber (Eagle Group), Gupta Synthetics Limited & Century Enka Limited as “supporters”. Updated Petition seems to “include” another supporter- M/s Orilon India. No letter of support has been appended in this regard.
- ii. All producers and supporters must supply their injury data and the same must be considered in the industry-wise injury assessment

**C.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

19. The application has been filed by M/s JCT Ltd, M/s Gujarat State Fertilizer Chemicals Ltd (GSFC), M/s Gujarat Polyfilms Pvt. Ltd. (GPPL), M/s Praful Overseas Pvt. Ltd, and M/s AYM Syntex Limited and was supported by Salasar Polytex, JPB Fiber (Eagle Group), Gupta Synthetics Limited, Orilon India Pvt Limited and Century Enka Limited. There are no other producers of the subject goods apart from the applicants and the supporters.

20. The application has been filed by M/s JCT Limited, M/s Gujarat Polyfilms Pvt Ltd, M/s Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd, M/s Praful Overseas Pvt. Ltd & AYM Syntex (Formerly known as Welspun Syntex). There are five other Indian producers of the product, namely, Salasar, JPB Fiber, Gupta Synthetics Limited, Century Enka, and Oriilon India Pvt Ltd. All the other producers have supported the application. The petitioners have neither imported the subject goods nor are they related to any importer or exporter of the subject goods, except for M/s JCT Limited and M/s AYM Syntex, who have imported small amount of product under consideration (around 148 MT and 117 MT respectively) from the subject countries. Their import constitutes insignificant share of their own production as well as total Indian production and therefore they have been considered as eligible domestic producers. Further, the production by the applicants constitutes ‘a major proportion’ of Indian production of the like product. . It is, thus, determined that the application has been made by and on behalf of the domestic industry and the application satisfies the requirements of ‘standing’ under Rule 5 of the AD Rules. Further, the applicants constitute ‘Domestic Industry’ in terms of Rule 2(b) of the AD Rules.

**D. Miscellaneous submissions****D.1. Views of the Domestic Industry**

21. The following miscellaneous submissions have been made by the Domestic industry:

- i. Investigation was initiated vide Notification dated January 2017, well before expiry of existing ADD. The only bar on Designated Authority under Section 9A(5) is that the sunset review must be initiated before expiry of ADD which has been done in the instant case. The domestic industry has claimed confidentiality only where warranted and under the guidelines as established by the relevant

laws. As regards exemption being sought on NFY 170/24 and 280/14 for warp knitting it is submitted that NFY 170/24 and 280/14 are attracting benchmark price of duty. As regards inconsistency with article 5.3 of ADA it may be noted that Rule 5 and Article 5.3 are not applicable in case of sunset review.

- ii. It is a settled principle of anti-dumping law that demand supply gap does not justify dumping. Imposition of ADD does not bar imports.

## **D.2. Views of other interested parties**

22. The following miscellaneous submissions have been made by other interested parties in this regard –
  - i. Extension of duty cannot be done after the expiry of original customs notification. Extension of AD duty in the interim of the sunset review has been done illegally. The notification came out on 19th which is after the expiry of original duties and cannot be retrospectively applied.
  - ii. Excessive confidentiality has been claimed. Construction of normal value and export price is flawed.
  - iii. Excessive confidentiality has been claimed. Construction of normal value and export price is flawed, the PCN wise calculations of the petitioners and lack of post-POI information is also to be looked into.
  - iv. Petition lacks evidence and is inconsistent with article 5.3 of ADA. Total sales exceed total domestic production, this shows there is calculation error. And it has also gained approximately 96% capacity utilization.
  - v. Petitioners have alleged non-cooperation by some exporters in the present case. However, these submissions appear to be incorrect as PT Susila Indah Synthetic Fiber Industries has in fact participated in the current investigation and has also been verified by the Authority.
  - vi. Basis of Petitioners' claim that Formosa was earlier engaged in dumping from Taiwan and has now shifted operations to Vietnam belies any logic. Formosa never participated in the investigation from Taiwan and so it is unclear if Formosa was ever involved in trading with India from their Taiwanese unit. Entire argument is make-believe and no real threat of "shifting of dumping source" is established. "Shift" of source of dumping, as claimed, is nothing more than a claim of circumvention of existing duties.
  - vii. Exemption from duty be given on NFY 170/24 and 280/14 for warp knitting as the same has been given to the same grade used for hook and loop tape fastener.

## **D. 3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

23. Various interested parties have raised several issues with respect to the present investigation, including methodologies of dumping determination and injury claims of the domestic industry. While the issues regarding the dumping and injury determination is addressed in the appropriate places, the general issues raised by the parties to the investigation are examined and addressed as provided hereunder:

- i. As regards the argument that the extension of duty cannot be done after the expiry original customs notification, it is noted that the Authority had duly initiated the investigation prior to the expiry of the anti-dumping duties as required under the law.
- ii. As regards the contention that the domestic industry cannot fulfill the demand of the warp industry it is noted that the claim has not been substantiated and in any case the imposition of anti-dumping duty does not prevent imports. All it does is to only remove the trade-distorting effect associated with the dumped import.
- iii. As regards the argument regarding the basis of petitioners' claim that Formosa was earlier engaged in dumping from Taiwan and has now shifted operations to Vietnam, the Authority notes that the imports from subject countries have declined and, in fact, imports have started entering the domestic market in significant volume from Vietnam. Thus, the shift in dumping is clearly visible.
- iv. As regards the argument that petition lacks evidence and is inconsistent with article 5.3 of ADA, the Authority notes that the domestic industry had filed a duly substantiated application and the Authority after prima facie satisfaction only initiated the investigation.

- v. As regards the contention on excessive confidentiality the Authority notes that the information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Further, wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.

**E. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**

**E.1. Views of the Domestic industry**

24. The domestic industry inter alia submitted as follows:

- i. One of the provisions of Accession protocol has expired on 11<sup>th</sup> December, 2016. The Designated Authority should however proceed with present investigation considering Chinese producers as producers operating in non-market economy conditions due to reasons given below.
- ii. The investigation period considered by the Authority in the present case is April 2015 to September 2016 (18 months).
- iii. The purpose of fixation of POI is to consider a period when the existence of dumping causing injury is claimed and established..
- iv. The Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies for the reason that the costs and prices in China do not reasonably reflect the market forces. Para 8 to Annexure-I specifies the parameters which should be considered for grant of market economy status.
- v. Since Chinese companies have been denied market economy status for the reasons mentioned in Para 8 of Annexure-I till December, 2016, petitioner submits that the Chinese producers are required to be treated as non-market economy companies till such time the investigation period includes the period specified in Accession protocol.
- vi. Chinese producers are required to be treated as companies operating under non-market economy environment and the Authority may proceed to determine the normal value on the basis of Para 7 of Annexure-I.
- vii. Normal value could not be determined on the basis of price of like article in an appropriate market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available. The petitioner has claimed consideration of normal value on the basis of cost of production in India duly adjusted.
- viii. The dumping margin from China is not only significant, but also substantial, thus establishing existence of significant dumping of the product under consideration in India. The import volume of China has remained significant throughout the present injury period, despite anti-dumping duty in force.
- ix. Considering the production capacities available with Chinese producers and their high export orientation, dumping would continue and even intensify in the event of cessation of anti-dumping duty.
- x. For Chinese Tapei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Korea RP also the petitioners have claimed normal value on the basis of cost of production in the exporting countries, duly adjusted.

**E.2 Views of the interested parties**

25. The following submissions have been made with regard to normal value, export price and dumping margin –;

- i. Petitioners have failed to divulge the basis of the calculations for Normal Value and the source of best estimates. Petitioners also failed to mention what factors were considered as “relevant”. Petitioners have ignored liability of establishing adjustments for export price by way of evidence. Assumption

that revocation of duty would pose a threat is not evidenced by data of Petitioners or borne out of imports from Indonesia.

- ii. Basis of Petitioners' claim that Formosa was earlier engaged in dumping from Taiwan and has now shifted operations to Vietnam belies any logic. Formosa never participated in the investigation from Taiwan and so it is unclear if Formosa was ever involved in trading with India from their Taiwanese unit. Entire argument is make-believe and no real threat of "shifting of dumping source" is established.

### **E.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

#### **E.3.1 Examination of Market economy claims**

26. At the stage of initiation, the petitioners proceeded with the presumption by treating China PR as a non-market economy country. Upon initiation, the Authority advised the producers/exporters in China to respond to the notice of initiation and provide information relevant to determination of whether their data/information could be adopted for the purpose of normal value determination. The Authority sent copies of the questionnaire to all the known producers/ exporters for providing relevant information in this regard. However, none of the Chinese producers/exporters have filed any response.

27. The Authority notes that none of the producers and exporters of the subject goods from the subject country have submitted the exporter's questionnaire response and supplementary questionnaire response. In view of non-cooperation, the Authority is unable to determine normal value in case of China PR on the basis of their questionnaire response.

28. Further, none of the interested parties, including the Domestic Industry, has made available any material fact to the Authority to determine normal value on the costs or price in China. The Authority has, therefore, determined normal value in respect of China PR on the basis of best information available, in terms of rule 6(8) of the Rules.

#### **E.3.2 Determination of Normal Value for producers and exporters in China PR**

29. In view of the above, Normal value for the subject goods imported from China PR into India has been constructed considering optimum consumption norms of the domestic industry for raw materials and utilities, conversion cost, interest, SGA, etc. at the levels allowed for the domestic industry including thereupon reasonable profit. Separate normal value has been determined for each PCN.

#### **E.3.3 Determination of Export Price for China PR**

30. The Authority notes that none of the exporters from China PR has furnished information to the authority which could be used for determination of export price and individual dumping margin. Therefore, the Authority has determined export price for producers/exporters from China on the basis of the DGCIS transaction-wise data. The export price has been adjusted on account of Ocean Freight, Marine Insurance Commission, Bank Charges, Port Expenses and Inland Freight Charges to arrive at the net export price at ex-factory level. Accordingly, the net export price at ex-factory level for exports from China PR is as shown in the dumping margin table below :-

Particular	UOM	China PR
Net export price/MT	USD/MT	***
Normal Value	USD/MT	***
Dumping Margin	USD/MT	***
Dumping Margin	%	20-30%

#### **E. 3.4 Determination of Normal value for Indonesia**

31. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters, advising them to provide information in the form and manner prescribed. Response to questionnaire was filed by the following producer/exporter from Indonesia.

- a. PT. Indachi Prima, Indonesia
- b. Sulindafin, Indonesia

32. In view of questionnaire response from the producers/exporters in Indonesia, normal value and dumping margin in case of responding producers & exporters has been determined on the basis of their questionnaire response.

33. From the Exporter Questionnaire (EQ) response, the Authority notes that M/s PT. Indachi Prima, Indonesia is a producer/exporter of the subject goods to India. As per information filed by the exporter and verified by the authority, during the Period of investigation PT. Indachi Prima, sold \*\*\* MT subject goods in the domestic market. The authority has considered cost of production of the company for each PCN and determined whether the selling price in the domestic market was viable and representative. In all those cases where more than 80% sales for the PCN was profitable, all sales have been considered in determining Normal Value. In all those cases where less than 80% sales for the PCN was profitable, profitable sales have only been considered in determining Normal Value. Price adjustments on account of taxes, commission, inland freight and credit cost has been claimed and has been allowed after due verification. PCN wise normal value has been determined for the PT. Indachi Prima, Indonesia. Weighted average Normal Value has been determined as \*\*\* USD per MT

34. In the exporter's questionnaire response filed by M/s Sulindafin, no export sales to India during POI has been reported. Accordingly, no individual margin or treatment can be given to Sulindafin, Indonesia.

#### **E. 3.5 Export price for PT. Indachi Prima, Indonesia**

35. Export price for PT Indachi Prima has been determined on the basis of questionnaire response filed by the exporter and verified by the authority. The producer/exporter has exported \*\*\* MT of subject goods to India during POI at a weighted average net export price of \*\*\* USD /MT. Adjustments have been considered on account of Credit cost, Inland Freight, Commission, Customs Handling Charges, ocean freight, and Bank Charges to determine net export price at ex-factory level, which have been verified and allowed to determine ex-factory export price. Separate export price has been determined for each PCN exported to India.

#### **E. 3.6 Normal Value & Export Price for non-cooperating producers/exporters in Indonesia**

36. For the other producers/exporters of Indonesia, Normal value has been determined on the basis of facts available while the export value has been considered on the basis of the cooperative exporter's data on exports to India. Based on this the dumping margin is indicated in the relevant table.

#### **E. 3.7 Determination of Normal value for Malaysia**

37. The Authority sent questionnaires to the known producers/exporters, advising them to provide information in the form and manner prescribed. Response to questionnaire was filed by the following producer/exporter from Malaysia.

- a. M/s Recron (Malaysia) Sdn Bhd, Malaysia

38. Exporter Questionnaire Response has been filed by M/s Recron, Malaysia. It is however noted that the domestic sales of the subject goods by the responding exporter/producer in its home market is below 5% of the export volume to India and thus not representative enough for determination of normal value on the basis of its domestic selling price and thus the ordinary course of trade test criterion has not been satisfied. Thus, PCN wise normal value has been determined for responding exporter/ producer on the basis of cost of production of the exporter and reasonable profit @5%.

#### **E. 3.8 Export Price for Recron (Malaysia) Sdn Bhd, Malaysia**

39. Export price has been determined on the basis of questionnaire response filed by the exporter and verified by the authority. The producer/exporter has exported \*\*\* MT of subject goods to India during POI at a weighted average net export price of \*\*\* USD /MT. Adjustments have been considered on account of overseas freight, Inland Freight, Commission, Customs Handling Charges, container seal charges, interest cost, insurance and Bank Charges to determine net export price at ex-factory level, which have been verified and allowed to determine ex-factory export price. Separate export price has been determined for each PCN exported to India

**E. 3.9 Export Price for non-cooperating producers/exporters in Malaysia**

40. For the other producers/exporters of Malaysia, Normal value has been determined on the basis of facts available while the export value has been considered on the basis of the cooperative exporter's data on exports to India. Based on this the dumping margin is evaluated as indicated in the relevant table.

**E.3.10 Dumping Margin determination for Taiwan, Thailand and Korea****Normal Value for Taiwan, Thailand and Korea**

41. As none of the producers/exporters from Taiwan, Thailand and Korea have responded, the Authority has constructed the normal value for all producers/exporters on the basis of best available information in accordance with Rule 6 (8) by adopting cost of production in India considering optimum consumption norms of the domestic industry for raw materials and utilities, conversion cost, interest, SGA, etc. at the levels allowed for the domestic industry including reasonable profit. Separate normal value has been determined for each PCN.

**E.3.11 Export Price in Taiwan, Thailand and Korea**

42. As none of the producers/exporters from Taiwan, Thailand and Korea have cooperated, the DGC&S import data has been adopted for determining the CIF price. To evaluate the ex-factory export price, adjustments on account of ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, inland freight and port expenses has been made. To determine the landed value of imports, basic customs duty and cess have been applied on assessable value which is equivalent to CIF value of imports with 1% landing charges. Separate weighted average export price to India has been determined for each type of PCN.

**E.3.12 Dumping Margin**

43. The dumping margin for subject goods has been determined by comparing PCN wise normal value and net export price at ex-factory level for the subject goods. The table below shows the weighted average dumping margins for all the subject countries.

**Table**

Countries	Producer/Exporters	DM US \$/MT	DM %	DM % in Range
China PR	All producers/ Exporters	***	***	20-30
Indonesia	M/s PT Indachi Prima	***	***	65-75
	Others	***	***	115-125
Korea	All producers/ Exporters	***	***	20-30
Malaysia	M/s Recron	***	***	10-20
	Others	***	***	45-55
Taiwan	All producers/ Exporters	***	***	20-30
Thailand	All producers/ Exporters	***	***	20-30

44. It is seen that the dumping margins are more than the de-minimis limits prescribed under the Rules in respect of exports made from each of the subject countries.

**F. DETERMINATION OF INJURY AND CAUSAL LINK****F.1 Views of the Domestic industry**

45. As regards injury and causal link, the domestic industry has made submissions as under :

- i. The demand/apparent consumption of the subject goods have increased over the injury period including the POI. Imports from subject countries, though, have declined but still remained significant despite anti-dumping duty, both in absolute terms and in relation to production/consumption in India.
- ii. Demand of the subject goods has consistently increased over the injury period. The information regarding imports volume and market share earlier provided shows that the imports have declined over the injury period. Market share followed the trend of volume of imports.
- iii. The imports are undercutting the domestic prices significantly. The extent of undercutting has increased over the injury period. With respect to price suppression/depression, both cost of production and selling price have declined over the injury period, with the decline in selling price being more as compared to the decline in cost of production. Selling price continues to remain below the level of costs of production. Landed price of imports is much below the level of selling price and cost of production.
- iv. A comparison between the landed price of imports and non-injurious price shows that the landed price of imports is far below the non-injurious price in the period of investigation resulting in price underselling.
- v. The production and sales of the domestic industry has increased over the injury period. The capacity utilization of the domestic industry has also increased over the injury period. The level of inventories has remained in similar range and is significant. Petitioners have not claimed injury on account of volume parameters.
- vi. The financial losses suffered by domestic industry show a reducing trend throughout the injury period, however the losses remain significant. The product under consideration can be either mono-filament or multi-filament. In monofilament yarn, since there are low imports of the product from subject countries, domestic industry has earned profits and the profits have increased over the years. In multi filaments, since the product under consideration is being dumped from subject countries as well as other countries (against which investigation is being carried out), the domestic industry is suffering severe financial losses.
- vii. Separate injury analysis for multi filament yarns and mono filament yarns is illegal under the law. The injury analysis must be for the like article to the product under consideration.
- viii. The domestic industry suffered significant financial cash losses in multi filament yarn, whereas it has earned cash profits in mono filament, clearly establishing that the adverse effect on multi filament yarn is due to dumped imports.
- ix. The return on investment was negative in 2013-14 and has thereafter shown a positive trend. The ROI is however still much below even the banks rate of interest in India. The domestic industry has suffered significant negative return on capital employed in multi filament, whereas earned positive return on capital employed in mono filament, clearly establishing that the adverse effect on multi filament is due to dumped imports.
- x. The domestic industry has earned cash profits post 2013-14 but profits have not been enough to sustain the domestic industry.
- xi. The ROI turned positive only from 2014-15 and onwards but still remained at abysmally poor levels. The ROI is much below even the banks rate of interest in India.
- xii. The market share of DI in demand has remained at similar levels while there is a decline in market share of subject imports.
- xiii. The number of employees and wages paid declined. Productivity per day and per employee has increased over the injury period in consonance with the production.
- xiv. The dumping margin and injury margin is positive and significant. Antidumping duties have acted as a deterrent and have prevented the subject countries from aggressively dumping large volume of the goods into India. However, whatever volumes have been exported to India during the relevant period, are at dumped and injurious price.

- xv. Despite imposition of Anti-dumping duty and subsequent enhancement of the quantum of such duty in the Mid Term Review and extension of duties in the last conducted sunset review, product concerned continues to be imported at dumped prices. Import volumes have declined, however the same are at dumped price. The decline in import volumes is because of dumping additionally happening from other countries, which are now at present under investigation.
- xvi. Act and the Rules do not prescribe any time limit beyond which the anti-dumping duty should not be extended. The legal provision clearly is that the anti-dumping duty can be extended further from time to time, if it is found that dumping and consequent injury to the domestic industry is likely in the event of cessation of anti-dumping duty. Indian cases wherein duty extended for 15 years have been referred - Acrylic Fibre (Thailand & Korea RP); Acrylonitrile Butadiene Rubber (Korea RP); Vitamin C from China.
- xvii. The present sunset review investigation need not be confused with a fresh investigation. In a sunset review investigation there is no test of de-minimis. Even low volume of imports are at dumped and injurious price and the prices are undercutting the prices of the domestic industry.
- xviii. Imports continue to occur at dumped and injurious price which in itself shows the likely behaviour of exporters from subject countries. Factors such as likelihood of shifting of the source of dumping, ample production capacity of exporters and export orientation of foreign producers, dumping margins determined in all previous investigations, price attractiveness of Indian market and vulnerability of the domestic industry shows likelihood of continuation of dumping and injury.
- xix. No evidence has been provided to justify the claims regarding poor quality of yarn. The petitioners have been able to sell the subject goods and are suffering on prices that are taking the plunge caused by dumping.
- xx. The domestic industry has not been able to make only meagre profits despite imposition of antidumping duties. Innovation and investment in R&D in the event of cessation of dumping is not likely in the present scenario unless the domestic industry is protected from dumping.

## **F.2 Views of other interested parties**

46. Submissions made by the other interested parties are as under:
- i. Petitioners claimed to rely on IBIS data for the import data. The same is confusing as the petitioners in their petition stated that they will be relying on IBIS data as DGCI&S data was unreliable. Contrary to this, updated data relied on DGCI&S rather than IBIS. In written submission petitioners again state that only IBIS data has been used.
  - ii. The injury assessment done by Petitioners is based on data of the Petitioners without consideration of data of supporters. POI overlaps between October 2015 to September 2016 (1 year) in the current case as well as parallel fresh investigation. The risk of doubly remedying the same injury is very high in the present case.
  - iii. Dumping margin, injury margin and undercutting has been determined grade wise but mentioned under “other PCN”, basis of which is not clear.
  - iv. Separate injury analysis for multi filament yarn and mono filament yarn is required. Anti-Dumping duty in fixed duty form was imposed in NFY case with respect to multi filament yarn but benchmark price was applied with respect to mono filament yarn. The same should be continued.
  - v. Indonesian imports are not entering into India at depressive prices. With respect to multi-filament yarn, Indonesian imports are not entering into India at suppressed or depressed prices. Imports from Indonesia are predominantly of monofilament yarns, which admittedly have not caused injury to the Petitioners.
  - vi. Claim of continued injury to Indian industry is wrong. Price suppression and depression did not exist at the time of filing of Petition with respect to the POI but suddenly appeared while filing written submission.
  - vii. The petitioners failed to establish existence of any continued injury or likelihood of recurrence. Domestic industry is suffering from injury even when ADD imposed because of increased capacity leading to high interest costs and high depreciation.



- viii. The domestic industry has shown poor performance in the inter se competition with other domestic producers. Status of domestic industry will not be altered on removal of ADD.
- ix. Data highlights that volume of imports from subject countries is at an all-time low. Imports from the subject countries halved in volume in comparison to that in the base year and declined over POI. Imports from other countries have increased by 228%.
- x. Production and consumption of Indian producers have increased as against decline in imports. The petitioner's claim regarding price underselling as a factor for injury assessment is incorrect as the same is not admissible for analyzing the injury.
- xi. It is important to note the petitioner could not have maintained the market share of 42% in an expanding market as the market share of other Indian producers as well as that of imports from other countries have also increased.
- xii. Petitioner's economic parameters show positive trends and no injury. Production, capacity and capacity utilization are all increasing. Inventories were falling between 2012-13 and from thereon remained constant. Petitioners have claimed that profits have been made in monofilament yarns but significant cash losses are there in multi filament. Petitioners have withheld data pertaining to interest and depreciation costs. In the original petition it is clear that PBIT (Profit before interest and tax) is high. And so petitioners are not suffering losses due to suppressed selling price. There is no "injury" due to alleged dumping. Increased capital employed with respect to multi-filament yarns also indicates that interest costs are high. Petitioners have attributed low ROI to dumped imports but actually they have increased their capacity over the period of injury and so the capital employed has also increased.
- xiii. Conclusions regarding adverse effects of imports on profits, market share, cash profit and inventories are without any basis as profits have increased while losses have declined. Inventories have declined in comparison to increased production volume.
- xiv. No injury based on trend analysis of number of employees, wages paid and productivity per day and per employee is seen.
- xv. Imports from certain countries are less than the minimum required level and so China, Thailand and Indonesia should be excluded as collectively they are below 7% and individually below 3%
- xvi. Poor quality material used by the domestic industry has resulted in heavy losses and poor production efficiency. The same is also because of old and obsolete tech used by them.
- xvii. It cannot also be concluded that they are suffering from the ill impacts of dumping from Vietnam and EU.

### **F.3 EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

47. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties. The Authority has examined the submissions made by the domestic industry and other interested parties with regard to the injury in accordance with the Anti-dumping Rules.

48. For the examination of the impact of the imports on the domestic industry in India, the Authority has considered relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales quantum, stock, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II (iv) of the Rules.

49. The Authority has undertaken injury analysis on overall basis as per the existing practice and the anti-dumping rules despite PCN methodology having been adopted for appropriate comparison.

#### **F.3.1 Volume Effect of dumped imports and impact on domestic industry**

##### **A. Demand and Market Share**

50. The demand or apparent consumption of the product in India is the sum of domestic sales of all the Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	Annualised POI
Sales of Domestic Industry	MT	***	***	***	***
Sales of Other Indian Producers	MT	***	***	***	***
Imports from Subject Countries	MT	19,400	14,415	13,659	12,849
Imports from other countries under separate ADD investigation	MT	4,594	7,237	10,523	12,794
Imports from rest other Countries	MT	1,107	594	765	218
<b>Demand/consumption</b>	<b>MT</b>	<b>68,275</b>	<b>75,459</b>	<b>90,088</b>	<b>1,05,145</b>
<b>Market share in demand</b>					
Sales of Domestic Industry	%	43.27%	49.49%	44.61%	42.19%
Sales of Other Indian Producers	%	19.97%	21.03%	27.70%	33.21%
Imports from Subject Countries	%	28.41%	19.10%	15.16%	12.22%
Imports from other countries under separate investigation	%	6.73%	9.59%	11.68%	12.17%
Imports from Other Countries	%	1.62%	0.79%	0.85%	0.21%
<b>Demand/consumption</b>	<b>%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

51. The Authority notes that the demand for the product under consideration has increased throughout the injury period. The share of imports from subject countries in the demand/consumption has however declined. The share of the domestic industry in the demand has registered very marginal decline.

**B. Import volumes and share of subject countries**

52. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. The volume of imports of the subject goods from the subject countries have been analyzed as under:

Import Volume	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	Annualized POI
Subject Countries	MT	19,400	14,415	13,659	12,849
Imports from other countries under separate investigation	MT	4,594	7,237	10,523	12,794
Other Countries	MT	1,107	594	765	218
Total Imports	MT	25,101	22,247	24,946	25,860
<b>Market Share in Imports</b>					
Subject Countries	%	77.29%	64.80%	54.75%	49.69%
Others	%	22.71%	35.20%	45.25%	50.31%
Total Imports	%	100.00	100.00	100.00	100.00
Indian Production	MT	***	***	***	***
Demand	MT	68,275	75,459	90,088	1,05,145
Imports from subject countries in relation to-					

Indian Production	%	45.35%	26.54%	20.74%	16.12%
Consumption	%	28.41%	19.10%	15.16%	12.22%

53. It is noted that the import volume from subject countries has declined over the injury period in absolute terms. Imports from other countries under separate ongoing anti-dumping investigation have increased.

54. The volume of imports were further examined by segregating imports into mono and multi filament. It is seen that while volume of mono filament yarn imports have significantly declined, volume of multi filament yarn has more or less remained at the same level, as is evident from table below

Particulars	UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI (Annualised)
Dumped import from subject countries	MT	19400	14415	13659	12849
Mono Filament Yarn	MT	7290	2596	1536	959
Multi Filament Yarn	MT	12109	11819	12123	11890

### F.3.2 Price Effect of dumped imports and impact on domestic industry

55. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from subject countries has been examined with reference to the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of production, Net Sales Realization (NSR) and the Non-injurious Price (NIP) of the Domestic industry have been compared with the landed cost of imports from subject countries. The Authority has carried out the analysis of price undercutting and price underselling on PCN basis as there is significant variation in the per kg prices of various PCNs.

#### a) Price Undercutting

56. For price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and the average selling price of the domestic industry net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level.

Particulars	Unit	China	Indonesia	Korea	Malaysia	Taiwan	Thailand
Landed price of imports	Rs/MT	190,282	188,643	171,467	160,614	175,455	174,334
Net Selling Price	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Price Undercutting	%	5-15%	10-20%	20-30%	25-35%	15-25%	15-25%

57. The Authority notes that during the POI, the price undercutting effect of the alleged dumped imports is positive in respect of all subject countries.

**b) Price Underselling**

58. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from subject countries. The comparison has been made on PCN wise and weighted average of all the calculations is as follows:

Particulars	Unit	China	Indonesia	Korea	Malaysia	Taiwan	Thailand
Landed price of imports	Rs/MT	190,282	188,643	171,467	160,614	175,455	174,334
Non Injurious Price	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Price Underselling	Rs/MT	***	***	***	***	***	***
Price Underselling	%	10-20%	10-20%	15-25%	25-35%	20-30%	15-25%

59. It is noted from the above table that there is price underselling on account of imports of the subject goods from the subject countries

60. **Price suppression and depression effects of the dumped imports:** In order to determine whether the dumped imports are suppressing or depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree, the Authority considered the changes in the costs and prices over the injury period. The position on the basis of the cost of sales and selling price furnished by the domestic industry is shown as per the table below:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	Annualised POI
Cost of Sales	Rs./MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	100	96	81
Selling Price	Rs./MT	***	***	***	***
<i>Trend</i>	Index	100	102	100	85
Landed Price	Rs./MT	241,250	235,746	216,937	171,062
<i>Trend</i>	Index	100	98	90	71

61. It is seen that both, cost of sales as well as selling price has declined over the injury period. There is depression in selling price only during the POI, though not during earlier injury period. There is however more decline in cost than in the selling price.

**F.3.3 Examination of Economic Parameters relating to Domestic Industry**

62. Annexure II to the AD Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of these imports on domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.

63. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry are analyzed herein below:

**A) Actual and potential impact on Production, Capacity, Capacity utilization and Sales**

64. The performance of the domestic industry with regard to production, capacity, capacity utilization and sales are as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	Annualised POI
Capacity	MT	***	***	***	***
Production	MT	***	***	***	***
Capacity Utilization	%	81.15%	84.61%	88.10%	87.06%
Sales	MT	***	***	***	***
Demand/consumption	MT	68,275	75,459	90,088	1,05,145

65. The Authority notes that the domestic industry enhanced its capacity over the injury period in line with the increase in demand for the product under consideration in the country. Production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry have also increased over the injury period.

**B) Market Share in demand**

66. The effects of the dumped imports on the market share of the domestic industry have been examined as below. It is noted that the market share of the domestic industry has declined but of other Indian producers has witnessed substantial increase.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Sales of Domestic Industry	%	43.27%	49.49%	44.61%	42.19%
Sales of Other Indian Producers	%	19.97%	21.03%	27.70%	33.21%
Imports from Subject Countries	%	28.41%	19.10%	15.16%	12.22%
Imports from Other Countries	%	8.35%	10.38%	12.53%	12.37%
Demand/consumption	%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

**C) Inventories**

67. The Authority further notes that the average inventory levels of the domestic industry have remained almost the same throughout the injury period.

Particulars		UOM	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Average Stock		MT	***	***	***	***

**D) Profits, return on investment and cash flow**

68. Performance of the domestic industry with regard to profit, return on investment and cash flow is as follows:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Profit/( Loss) per unit	Rs./MT	***	***	***	***
Profit/( Loss) per unit	Indexed	(100)	(52)	(5)	14
Profit/( Loss) - total	Rs.Cr	***	***	***	***
Profit/( Loss) - total	Indexed	(100)	(66)	(6)	21
<b>Mono filament Yarn</b>					

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Profit/( Loss) per unit	Rs./MT	***	***	***	***
Profit/( Loss) per unit	Indexed	100	14	17	132
Profit/( Loss) - total	Rs.Cr	***	***	***	***
Profit/( Loss) - total	Indexed	100	15	19	147
<b>Multi filament Yarn</b>					
Profit/( Loss) per unit	Rs./MT	***	***	***	***
Profit/( Loss) per unit	Indexed	(100)	(38)	(7)	(19)
Profit/( Loss) - total	Rs.Cr	***	***	***	***
Profit/( Loss) - total	Indexed	(100)	(50)	(10)	(30)
Profit before Interest and Tax	Rs.Cr	***	***	***	***
Profit before Interest and Tax	Indexed	(100)	350	750	950
Mono Filament	Rs.Cr	***	***	***	***
Mono Filament	Indexed	100	47	47	126
Multi Filament	Rs.Cr	***	***	***	***
Multi Filament	Indexed	(100)	23	100	59
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Return on Capital Employed	Indexed	(100)	349	770	840
Mono Filament	%	***	***	***	***
Mono Filament	Indexed	100	47	53	132
Multi Filament	%	***	***	***	***
Multi Filament	Indexed	(100)	19	79	43

69. It is noted that domestic industry is earning profits in mono filament yarn wherein imports is low and suffering losses in multi filament yarn where imports are relatively more. Similarly, return on investment is much less in Multi filament yarn as compared to mono-filament yarn. However, on overall aggregated basis, there has been improvement in rate of return as well as profitability

#### **E) Productivity**

70. It is seen from the table below that productivity in terms of, productivity per day as well as per employee, has increased over the injury period, which is in line with the movement of production:

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Productivity Per day	MT/Day	***	***	***	***
Productivity Per employee	MT/Nos.	***	***	***	***

#### **F) Employment and wages**

71. It is noted from the table below that the employment with the domestic industry has declined during the injury period. However, wages paid have increased. The Authority notes that these parameters are dependent on a number of other parameters and not reflective of impact of dumping on the domestic industry.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI
Employment	Nos	***	***	***	***
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***

**G) Growth**

72. The table below shows that the domestic industry has registered positive growth in terms of volume parameters, such as, sales volume, production, capacity utilization. Further growth in terms of price parameters for monofilament yarn has improved wherein imports have been low whereas in case of multi filament yarn has been negative where imports have more or less remained constant.

Particulars	Unit	2012-13	2013-14	2014-15	POI (A)
Production	%	-	27%	8%	9%
Domestic Sale	%	-	26%	8%	10%
Capacity utilization	%	-	3%	3%	-1%
Mono Filament Yarn					
profit	%	-	-85%	24%	680%
Return on investment	%	-	-53%	14%	147%
Multi Filament Yarn	%	-			
profit	%	-	50%	80%	-202%
Return on investment	%	-	119%	318%	-46%

**H) Ability to raise Capital Investment**

73. The domestic industry has enhanced capacity for production of product under consideration considering the present and potential demand for the product in the country.

**I) Level of dumping & dumping margin**

74. It is noted that imports from the subject countries are still entering the country at dumped prices.

**J) Factors affecting domestic Prices**

75. The examination indicates that there is a healthy demand in India for the subject goods. It is also noted that the landed value of subject goods from subject countries are below non injurious price and selling price of the domestic industry. Petitioners have submitted that imports from other countries namely, EU and Vietnam are also entering the market at dumped and injurious price.

**K) Magnitude of Injury and Injury Margin**

76. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority in terms of Annexure III to the AD Rules has been compared with the landed value of the imports from the subject countries for determination of injury margin during the POI and the injury margin so worked out is as under:

Particulars	US\$/MT
Exchange Rate	***
Non Injurious Price (NIP)	***
Landed Price	2571.15
Injury Margin	***

Injury Margin-%	***
Injury Margin (Range)	20-30%

**L) Other Known Factors & Causal Link**

77. Having examined the existence of continued injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting and price suppression and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined by the Authority to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry, as follows:

**a) Volume and prices of imports from third countries:**

78. The Authority notes that imports entering into the country from European Union and Vietnam are above de minimis level and a separate ongoing antidumping investigation is underway. Imports from Vietnam and EU are also in multi filament category.

**b) Contraction of demand**

79. There has been rise in demand of the product concerned over the injury period. .

**c) Changes in the pattern of consumption**

80. The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the Domestic Industry.

**d) Developments in technology**

81. Technology for production of the product concerned has not undergone any change. Thus, developments in technology cannot be regarded as a factor causing injury to the domestic injury.

**e) Conditions of competition and trade restrictive practices**

82. There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the Domestic Industry.

**f) Export performance of the domestic industry**

83. The performance of the domestic industry and injury thereto has been examined with respect to the domestic performance to the extent possible. Possible deterioration in the export performance of the domestic industry is, therefore, not a possible cause of injury to the domestic industry.

**g) Performance of other products produced and sold by the domestic industry**

84. The performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performance. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

**h) Productivity of the domestic industry**

85. The Authority notes that the productivity of the domestic industry has followed the same trend as production and shows increase. Deterioration in productivity is not a cause of injury to the domestic industry.

**Factors relating to causal link**

86. The Authority notes that:

- There has been dumping of the product under consideration.
- The price undercutting effect of the dumped imports is positive in respect of all subject countries.
- There has been by and large improvement in the health of the domestic industry on all relevant economic parameters except in profitability.



- Overall profitability too has shown consistent improvement. However, it is mainly on account of the better performance in mono filament yarn segment where the import from subject countries has been relatively much less.

#### **G. POST DISCLOSURE STATEMENT SUBMISSIONS BY THE INTERESTED PARTIES**

87. The post disclosure submissions have been received from various interested parties. Majority of the issues raised therein have already been raised earlier during the investigation and also addressed appropriately. Additional submissions have been analysed as under:

##### **Submissions made by the Domestic Industry**

88. The submissions made by the domestic industry have been summarized as below:

- i. Analysis of Likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury is the most critical examination in a sunset review investigation. However the Disclosure Statement is completely silent on essential facts on such critical aspect of the investigation. Issuance of Disclosure Statement has become redundant to the extent that the domestic industry is not able to comment on the appropriateness of the facts being considered for determination of likelihood.
- ii. The emerging conclusions from the disclosure statement are –
  - a. The petitioners and domestic producers are eligible domestic producers of subject goods in India and their production constitutes a major proportion of Indian production.
  - b. The PUC is exported at prices below normal value, resulting in continued dumping from the subject countries.
  - c. Imports continue to cause injury to the domestic industry, as established by its performance over the period.
  - d. Performance of domestic industry in monofilament has improved where imports declined sharply and are low in volume and performance in multi filament yarn has deteriorated where imports are significant and dumping continues.
  - e. Anti-dumping duty is required to be continued to address dumping causing injury to the domestic industry.
- iii. PUC is Synthetic Filament Yarn of Nylon, also known as Polyamide Yarns (also described as Nylon Filament Yarn and also referred to as subject goods). Nylon Filament Yarn is a synthetic filament yarn produced by polymerization of organic monomers. The present investigation being a sunset review investigation and anti-dumping duties, as earlier recommended by the Authority, being in force on the imports of the subject goods from the subject countries, it has been rightly considered that the scope of PUC remain the same as that in the original and subsequent review investigation and therefore the argument by the other interested parties on exclusion of mono filament yarn from scope of PUC has been rightly discarded. There is continued injury in case of multi filament yarn. Mono filament yarn continues to be a significant portion of domestic operations as well as that of the exporters operation.
- iv. Application was filed by M/s JCT Limited, M/s Gujarat Polyfilms Pvt Ltd, M/s Gujarat State Fertilizers and Chemicals Ltd, M/s Prafful Overseas Pvt. Ltd & AYM Syntex (formerly known as Welspun Syntex) and was supported by Salasar, JPB Fiber, Gupta Sythetics Limited, Century Enka, and Oriilon India Pvt Ltd. No imports have been made by any petitioners except M/s JCT Limited and M/s AYM Syntex and that too are insignificant and does not render the said companies to be ineligible for being considered as Domestic Industry
- v. Production by the petitioners constitutes a majority of Indian production. Petitioners constitute eligible domestic industry within the meaning of Rules.
- vi. POI falls between April 2015 to September 2016 (18 months) and this period is well before the expiry of Chinese Accession Protocol so interested parties should have no objection to the method of calculation of normal value or that China has been treated as a non-Market Economy. No exporter/producer from China has filed questionnaire response.

- vii. Actual cost of production of the domestic industry be considered as normal value, which is based on best available information. Kindly revise the normal value and dumping margin.
- viii. Demand has increased throughout the injury period. Imports from the subject countries have remained quite significant, while dumped imports from other countries have increased.
- ix. Price undercutting and injury margin are positive.
- x. Landed prices are much below the selling prices and the NIP of the domestic industry and thus undercutting and underselling the prices of the domestic industry.
- xi. Price depression is caused by dumped imports.
- xii. Analysis regarding decline in cost is more than the selling price is incomplete. Selling price has declined more than the decline in costs in the POI as compared from the previous year. The fact that the domestic industry is in the process of recovering from the past ill effects of dumping is an injury parameter showing injury in the present case.
- xiii. Selling price continues to remain below the level of cost of production. Landed price of imports is much below the level of selling price and cost of production. Cessation of duty is likely to intensify losses already being suffered.
- xiv. Production, sales and capacity utilization of the domestic industry increased over the injury period.
- xv. Inventories have remained in similar range and is significant.
- xvi. Domestic Industry is suffering losses throughout the injury period because of dumping. Financial losses suffered show a reducing trend throughout the injury period, however they remained significant. The domestic industry has suffered financial losses in multi filament yarn, whereas earned profits in mono filament where imports have steeply declined, clearly establishing the adverse effect in multi filament is due to dumped imports.
- xvii. Productivity per day and per employee has increased over the injury period, which is in line with the movement of production.
- xviii. Growth parameters show that growth in mono filament yarns has improved whereas in multifilament yarns it has declined.
- xix. Dumping margin and injury margin worked out by the Authority is positive and significant. Whatever volume has been exported to India during the relevant period is at dumped prices and injurious price.
- xx. Being a Sunset Review investigation, the Authority has failed to address the issue of likelihood or continuation/recurrence of dumping altogether and so petitioners reiterate the submissions on likelihood of dumping and injury.
- xxi. Imports are having positive dumping margin and injury margin during the POI, indicating the likelihood of dumping and injury in the event of cessation of duties. In several past cases, wherein upon finding positive injury margin during the POI, Authority held that cessation of duty will lead to likelihood of dumping and injury.
- xxii. Designated Authority as a quasi-judicial Authority bound by past determination unless established either on basis of different legal proposition or facts of the case that past determinations are not binding and need to be ignored. Designated Authority is a quasi-judicial authority as held by the Hon'ble Supreme Court in the matter of ATMA vs. Designated Authority.
- xxiii. Designated Authority has held that anti-dumping duties are required to be extended further when the price undercutting, dumping margin and injury margin are positive; when domestic industry is suffering injury, whether from present or other sources; when continued injury to domestic industry is not from factors other dumped imports. The same fully exist in the present case.
- xxiv. Domestic Industry is suffering injury from dumped imports from Vietnam and European Union but the fact that it is suffering injury from dumped imports from some other sources does not per se imply that there is no likelihood of dumping or injury to it from the present sources.
- xxv. Dumping is already established in the disclosure statement. In such a case it is entirely immaterial whether dumping is from one dumped source or other dumped source. While considering injury to

- Domestic Industry, source of dumped import is not relevant. Notice of initiation issued in Vietnam and European Union clearly establishes acceptance by the Designated Authority that injury to the Domestic Industry is due to dumped imports.
- xxvi. In SSR case Designated Authority cannot decide on likelihood without examining behavior of exporters in individual export transactions to various countries globally. In the instant case even after calling for information the same has not been adopted in disclosure statement. Authority kindly consider the questionnaire response part II filed by responding exporters and in particular invoice by invoice details of exports made by responding exporters to various countries globally. Authority kindly determine dumping and injury margin in individual export transactions to third countries and such dumped imports must be considered separately and then cumulated to determine individual dumping margin in third country exports.
- xxvii. Imposition of ADD on the subject countries partly led to shift in dumping from other countries. Formosa Industries Corp. a group company of the Formosa Group operating a plant in Taiwan that produced the subject goods has shifted dumping through its company in Vietnam. It has responded in fresh investigation against subject goods in respect of Vietnam and EU. It was dumping from Taiwan and has now set up manufacturing facilities in Vietnam and therefore it is a clear case of dumping shifting from one source to another source.
- xxviii. Hyosung Corporation, a company in Korea manufacturing subject goods has shifted dumping through its related company in Vietnam.
- xxix. Authority itself noted in the Disclosure Statement that “imports have started entering the domestic market in significant volume from Vietnam thus the shift in dumping is clearly visible.” clearly establishing that in case current duties are removed and those on the fresh countries are levied the subject countries in the present investigations will again resort to the practice of dumping.
- xxx. Producers from subject countries have significant surplus capacities as compared to the demand of subject goods in subject countries. The same was held by the Authority in the last conducted sunset review investigation.
- xxxi. Authority is requested to kindly examine responses filed by exporters with respect to available capacity, export orientation and third country exports. It is likely that responses file by exporters would show likelihood of intensified imports in the event of cessation of anti-dumping duty.
- xxxii. Previous investigations established existence of significant dumping. Dumping margin determined for current investigation period is also substantially high clearly establishing that dumping is likely to continue and intensify in the event of cessation of present duty.
- xxxiii. Price at which subject goods are being exported by China to India is an indicator of the likelihood of continuation of dumping and injury. Imports are significantly undercutting the price of Domestic Industry. Imports are being made at dumped and injurious price. With cessation of duties, Indian prices are likely to be too attractive to the Foreign Producers.
- xxxiv. Domestic Industry suffered injury from dumped imports for quite some time as confirmed by the determination of previous investigations clearly establishing that the domestic industry is vulnerable to injury from dumped imports. There is a possibility that expiry of duty will result in flooding of the material in Indian market.
- xxxv. Only one exporter had responded to the authority and has claimed absence of likelihood. Malaysian exporter filed no submissions and has not even claimed absence of likelihood. The company is suffering significant financial losses in its business relating to PUC and has low domestic sales and very significant exports to third countries which are understood to loss making, establishing likelihood of injury to Domestic Industry in the event of cessation of duty.
- xxxvi. Indonesian exporter contended that it is fully utilized and not likely to cause increased injury to Domestic Industry. It has suppressed vital facts and made false and misleading statements. It is sitting on rising inventories and is exporting significant volumes to third countries which are even at lower prices than India while it is understood to be suffering significant financial losses. Thus Domestic Industry as well as the exporters are suffering financial losses clearly showing that exporters are resorting to dumping and looking for market opportunities.

- xxxvii. Conditions as mentioned in the recently issued trade notice for SSR investigations are fully met in the present case as would be seen from the petition and questionnaire response of the exporters. Even going by the parameters laid down by the authority, facts of the case clearly show likelihood injury to Domestic Industry.
- xxxviii. Not necessary that all conditions should exist for continuation of duty. There are numerous cases wherein duty has been continued even when one or more parameters were satisfied.
- xxxix. The form of anti-dumping duty should be fixed quantum of anti-dumping duty (fixed form of duty) for all the forms of subject goods.
- xl. Duty be imposed in terms of US\$. Rupee has depreciated significantly and so the definitive duties may kindly be expressed in US\$.

#### **Submissions made by other interested parties**

- 89. The submissions made by the other interested parties have been summarized as below:

#### **Post disclosure submissions on behalf of PT Indachi Prima, Indonesia.**

- i. The subject goods have been subject to anti-dumping duty for over 10 years. The essential facts of the present case do not disclose any special circumstances warranting continuation of anti-dumping duty. This principle emerges from the Designated Authority's final findings dated 20 May 2013 in Dry Cell Batteries case where the Authority has held that it will be the endeavour of the Authority not to continue the duty beyond a period of 10 years.
- ii. Imports from Indonesia account for mere 2.68% in total imports and occupy a miniscule market share of 0.66%. Such low imports cannot cause any volume and price effects so as to cause injury. Rule 11 read with paragraph (iii) of Annexure II of the AD Rules mandates that where imports are below 3%, they cannot be cumulated with imports of other subject countries for assessment of injury. Imports from Indonesia should not be cumulated with imports of other subject countries.
- iii. In the past, in similar cases where imports were negligible, the Designated Authority terminated the sunset reviews. Such cases are Float Glass from China PR and Indonesia (Final findings dated 2 July 2015), where the review was terminated against Indonesia and Dry Cell Batteries from China PR (Final findings dated 20 May 2013) where the review was terminated against China PR and Pentaerythritol from China PR and Sweden (Final findings dated 25 March 2011), where the review was terminated against Sweden.
- iv. There is no volume effect and price effect from imports of mono filament yarns. There is no price suppression as well. The domestic industry is in significant profits in this segment and the return on investment in this segment is also very high.
- v. Growth in production, domestic sales, return on investment and profitability has improved significantly in the injury period.
- vi. Market share of the domestic industry is above 40% and that of the Indian producers is above 75% during the POI (A). Capacity utilization of the domestic industry is 87% during the POI (A). Decline in selling price is lower than decline in cost of sales, which indicates there is no price suppression.
- vii. There is absence of surplus capacity in Indonesia, absence of anti-dumping duty on exports of the subject goods from Indonesia and contraction of demand of mono filament yarn in India indicating that there is no likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury from Indonesia.
- viii. Injury information of domestic industry is not disclosed in the disclosure statement such as capacity, production, sales, productivity, average stock, employment and wages. Even indexed numbers of the same have not been provided. These figures should be disclosed as the domestic industry has not claimed any confidentiality on the same.
- ix. It is requested that anti-dumping duty on mono filament yarn and duty against Indonesia should be discontinued.
- x. If the Authority decides to continue the duty, duty on Nylon 6 monofilament yarn should be in the same form as has been done in the original investigation and the subsequent sunset review.

## **H. EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

90. The Authority notes that most of the submissions by parties are repetitive in nature and were already addressed earlier in the disclosure statement. The findings above deal with these arguments of the parties. Further, the Authority has examined submissions of interested parties herein below to the extent relevant and not addressed elsewhere:

- a) With regard to the submission made by the domestic industry that likelihood of dumping and injury examination ought to have been carried out, the Authority notes that there is no increase in the volume of dumped imports from the subject countries, leave alone significant increase. On the contrary, the volume of dumped imports have declined consistently. Similarly, the imports are certainly not causing significant depressing or suppressing effect on the domestic prices. The Authority further notes that examination of other parameters for likelihood of dumping and injury viz. availability of sufficient freely disposable capacity with the exporters in the subject country or the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian market, taking into account the availability of other exports markets to absorb any additional exports is an exercise akin to crystal ball gazing and the authority is not inclined to indulge in such an exercise. The Authority notes that there has been a clear and visible improvement in the performance of the domestic industry in respect of all economic parameters relevant for evaluation of injury.
- b) With regard to the submission that selling price of domestic industry is below the level of cost of production, the authority notes that the selling price as declared by the domestic industry was below the cost during the years prior to the POI. However, the situation has undergone a change during the period of investigation. During the POI, the selling price was well above the cost of production.
- c) With regard to the submission made by PT Indachi Prima that import from Indonesia are below 3% of the import of the product under consideration, the authority notes that Rule 14 of Anti-Dumping Rules does not apply to sunset review conducted under Rule 23.

## **I. RECOMMENDATIONS**

91. After examining the submissions made and issues raised, and considering the facts available on record, the Authority concludes that though the product under consideration has been exported to India from the subject countries below the normal value, it can be seen that the overall health of the domestic industry has improved and the anti-dumping duty in force during last 11 years (approx.) has served its intended purpose.

92. Therefore, the authority does not recommend continuation of the anti-dumping duty on the imports of subject goods from the subject countries.

93. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this Final Findings Notification shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

SUNIL KUMAR, Addl. Secy. & Designated Authority